



उदयपुर

Rashtradoot

कायदे, कानून व प्रक्रिया की पूरी जानकारी न होना भारी पड़ रहा है, भाजपा पर संसद में

जो हश्र “प्रिवलेज मोशन” का हुआ, वह ही अंजाम राहुल को डिस्क्वालिफाई करने के हल्ले का होगा?

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। भाजपा और निशिकांत दुबे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद से डिस्क्वालिफाई करने की मांग करके देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने की धमकी दी थी। लेकिन यह धमकी इसलिए वापस ले ली गई, क्योंकि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति अभी तक गठित ही नहीं हुई है। संभव है कि रिजिजू को भी इस बात की जानकारी नहीं थी।

विशेषाधिकार प्रस्ताव के लिए एक तय प्रक्रिया और नियम होता है। पहले विशेषाधिकार समिति अपनी रिपोर्ट देती है। इसके बाद मामला आचार समिति (एंथिक्स कमेटी) के पास जाता है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। इसलिए प्लान बी के तौर पर निशिकांत दुबे को आगे किया गया।

- “प्रिवलेज मोशन” नहीं लाया गया, क्योंकि “प्रिवलेज कमेटी” का अभी तक गठन नहीं हुआ है। प्रिवलेज कमेटी प्रस्ताव का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देती है, जो “एंथिक्स कमेटी” के सामने प्रस्तुत होती है। “एंथिक्स कमेटी” की सिफारिश के बाद, निर्णय लिया जाता है, किसी व्यक्ति के खिलाफ “प्रिवलेज मोशन” लाया जाए या नहीं। जब “प्रिवलेज कमेटी” का गठन ही नहीं हुआ अभी तक, तो “प्रिवलेज मोशन” की कार्यवाही आगे कैसे बढ़ती।
- इसी प्रकार निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को “डिस्क्वालिफाई” करने की मुहिम शुरू की। पर, यह स्पष्ट नहीं था कि राहुल गांधी को किस “रूल” के अंतर्गत “डिस्क्वालिफाई” करने की मांग की जा रही है या किस प्रक्रिया के जरिए राहुल गांधी को डिस्क्वालिफाई करने का प्रयास किया जा रहा है।
- निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायतों की लाइन लगा दी, शून्यकाल में। पर, ये शिकायतें किसी भी “लैटर हैड” पर नहीं लिखी गई थीं तथा शिकायत पत्र पर किसी भी सांसद के हस्ताक्षर नहीं थे तथा यह भी स्पष्ट नहीं था कि यह शिकायत पत्र किस के पास भेजा जाए।

उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया जाए। लेकिन किस प्रस्ताव के तहत? किस नियम के तहत? किस प्रक्रिया के तहत? खुद सांसद को ही इसकी

जानकारी नहीं है। उन्होंने विपक्ष के नेता के खिलाफ शिकायतों की लंबी सूची लिखी और उसे शून्य काल में पढ़कर सुना दिया। जिस कागज पर शिकायत लिखी

गई, वह न तो कोई लेटरहेड था और न ही उस पर कोई हस्ताक्षर। यह शिकायत किसे संबोधित की गई थी? किसी को भी इसकी जानकारी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सावलकोट पावर प्रोजैक्ट पर काम शुरू होने से घबराया पाकिस्तान

पाकिस्तान ने फिर से भारत पर पानी रोकने का आरोप लगाया

-श्रीरंज झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। भारत-पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल कम होता नज़र नहीं आ रहा है और आने वाले समय में भी इसके शांत होने की संभावना कम दिखती है।

पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत पर इस्लामाबाद के खिलाफ “पानी रोकने की नीति” अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं, भारत का कहना है कि उसे अपने क्षेत्र के अंदर बुनियादी ढांचा बनाने और सिंधु नदी की सहायक नदियों के बेहतर प्रबंधन का पूरा संप्रभु अधिकार है।

पाकिस्तान की ताजा आपत्ति चिनाब नदी पर 5129 करोड़ रुपये की लागत वाली सावलकोट जलविद्युत परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने की खबरों के बाद सामने आई है। पाकिस्तान ने कहा है कि वह भारत की

- भारत सरकार ने कहा, उसे अपने क्षेत्र में नदियों पर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का पूरा अधिकार है। इसके लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
- इथर पाकिस्तान ने कहा कि उसकी पानी की तीन चौथाई जरूरत चिनाब जैसी नदियों से पूरी होती है, और भारत द्वारा बाँध बनाने से उसका पानी रुक जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि भारत सरकार ने चिनाब पर 5129 करोड़ रूपए की लागत से सावलकोट पन बिजली योजना शुरू की है।

इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय कानूनी मंचों पर चुनौती देगा। पहलगाम हत्याकांड और उसके बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इसके बाद भारत ने जम्मू-कश्मीर में कई जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया है और कहा है कि अपने बुनियादी ढांचे का प्रबंधन

करना उसका संप्रभु अधिकार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा कि देश के भीतर शुरू की गई किसी भी विकास परियोजना का फैसला हमारी अपनी समझ के आधार पर होता है। नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा सावलकोट बांध, सिंधु जल संधि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बांग्लादेश चुनावों से गायब हैं महिला नेता

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। बांग्लादेश के चुनावी परिदृश्य में नाटकीय बदलाव आया है। कभी शेख हसीना और खालिदा ज़िया जैसी प्रभावशाली महिला नेताओं से पहचाने

- शेख हसीना और खालिदा ज़िया जैसी सशक्त महिला नेताओं का नेतृत्व देख चुके बांग्लादेश के आम चुनावों में मात्र 4 प्रतिशत महिलाएं ही चुनाव मैदान में दिखीं।

जाने वाले देश में अब मतपत्रों पर महिलाएं लगभग नदारद हैं। देशभर में केवल 4 प्रतिशत उम्मीदवार महिलाएं हैं, जिनमें से कई केवल पुरुष नेताओं से जुड़ी प्रतीकात्मक उम्मीदवार मानी जा रही हैं।

जहां कुछ इस्लामी दलों ने (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी फिल्म “घूसखोर पंडित” का नाम बदलने का नोटिस दिया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी फिल्म “घूसखोर पंडित” के निर्माताओं को इसके कथित जातिसूचक शीर्षक को लेकर नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि “फिल्म का नया नाम बताइए, नहीं तो रिलीज की अनुमति नहीं दी जाएगी।”

नीरज पांडे द्वारा निर्देशित और मनोज बाजपेयी अभिनीत फिल्म

- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फिल्म का नाम ब्राह्मण भावनाओं को आहत करता है। कोर्ट ने कहा, इसे बदलें, वरना रिलीज की अनुमति नहीं मिलेगी।

“घूसखोर पंडित” नैटफिलक्स पर रिलीज की घोषणा के बाद विवादों में घिर गई है। आरोप है कि फिल्म का शीर्षक ब्राह्मण समुदाय की भावनाओं को आहत करता है। अंग्रेजी में अनुवाद करने पर इस शीर्षक का मतलब एक भ्रष्ट ब्राह्मण होता है।

फिल्म निर्माताओं की ओर से पेश वकील ने अदालत को भरोसा दिलाया (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हिंसा व हत्याओं के वातावरण में बांग्लादेश में चुनाव सम्पन्न

पिछले चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी व जमात-ए-इस्लामी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के खिलाफ

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। भारत के पूर्वी पड़ोसी बांग्लादेश में गुरुवार को संसदीय चुनाव हुए, जो देशभर में गंभीर हिंसा और मतदान प्रक्रिया को लेकर अनिश्चितता के कारण प्रभावित रहे। यह पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरोध प्रदर्शनों के बीच, भारत आ जाने के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव है। मतपेटियों और मतदानकर्मियों को कड़ी सशस्त्र सुरक्षा के बीच मतगणना शुरू हो चुकी है। हालांकि, मतदान के दौरान कई गड़बड़ियों की खबरें सामने आईं। इसके अलावा, मतदान में आम लोगों की भागीदारी का स्तर भी कम रहा, जो मुश्किल से आधे से थोड़ा अधिक ही पहुंच पाया।

भारत में निर्वासित जीवन बिता रही हसीना ने चुनाव को फर्जी और एक ढोंग बताया। उन्होंने इसे रद्द करने की मांग की, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग को मतदान प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई और चुनाव लड़ने

- अब शेख हसीना की पार्टी चुनाव क्षेत्र में नहीं है, अतः बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी व जमात-ए-इस्लामी आमने-सामने मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में चुनाव लड़ रही हैं।
- भारत के लिए एक तरफ खड़ा और दूसरी तरफ खाई है, क्योंकि दोनों ही भारत विरोधी पार्टियां हैं, तथा बांग्लादेश से हिंदुओं को बाहर निकालकर फैंकना चाहती हैं। अजीबोगरीब बात है, जब बांग्लादेश, पाकिस्तान का हिस्सा था और पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, जब हिंदू विरोधी हिंसा व वारदातें कम होती थीं। ये घटनाएं अब कई गुना बढ़ गई हैं।
- बहरहाल, बांग्लादेश में वर्तमान गरीबी व कानून व्यवस्था भारत के लिए भारी संकट पैदा कर रही है, क्योंकि इस निर्धनता व बेरोज़गारी के कारण भारत के लिए पलायन करने वाले बांग्लादेशियों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है और भारत के लिए संकट व सुरक्षा का मुद्दा और गंभीर बनाता जा रहा है।

से भी रोक दिया गया।

इसके बजाय, विभिन्न स्तरों की

कट्टरपंथी सोच वाले राजनीतिक दलों (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा

लोकसभा सचिवालय ने कहा, ऐसा कोई प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्तावित विशेषाधिकार प्रस्ताव को लेकर जोर-शोर से शुरू हुए राजनीतिक ठकराव को हवा निकलती लग रही है। लोकसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव फिलहाल सक्रिय रूप से विचाराधीन नहीं है।

इस घटनाक्रम ने राजधानी में तीव्र राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया है, विशेषकर ऐसी खबरों के बाद, कि स्पीकर कार्यालय ने ऐसी किसी भी कार्रवाई से स्वयं को अलग कर लिया है।

विवाद की शुरुआत लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के तीखे भाषण के बाद हुई। अपने भाषण में, जिसमें आर्थिक आलोचना के साथ

- विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं लाए जाने पर यह चर्चा भी है कि स्पीकर के कार्यालय ने ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू करने से खुद का अलग कर लिया है।
- गुरुवार सुबह भी संसद का माहौल उस समय काफी उग्र हो गया, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य ठहराने की मांग कर दी।
- लेकिन शाम तक माहौल ठंडा पड़ चुका था, जब यह पता लगा कि न तो विशेषाधिकार प्रस्ताव का औपचारिक आवेदन आया है, न ही राहुल को “डिस्क्वालिफाई” करने का प्रस्ताव आया है।
- राजनैतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि सत्ता पक्ष का पीछे हटना उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि रणनीतिक कदम है। भले ही भाजपा राष्ट्रीय राजनीति में हावी है, पर, संसद में उसके पास प्रचंड बहुमत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष को डिस्क्वालिफाई करना न केवल उन्हें हीरो बना सकता है, बल्कि सहयोगी दलों को भी नाराज़ कर सकता है।

कड़ा राजनीतिक हमला भी शामिल था, गांधी ने कथित तौर पर तथाकथित “एस्पर्टोन फाइल्स” और उसके अंतरराष्ट्रीय संपर्कों का उल्लेख किया। सत्तापक्ष के सदस्यों के अनुसार, यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों की सीमा को स्पर्श कर रहा था। इसके तुरंत बाद, उनके भाषण के महत्वपूर्ण हिस्सों को संसदीय अभिलेखों से हटा दिया गया, और यह कदम स्वयं एक राजनीतिक विवाद का कारण बन गया।

गुरुवार सुबह राजनीतिक माहौल तब और गरमा गया, जब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जो अपने आक्रामक तेवरों के लिए जाने जाते हैं, को कथित तौर पर गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का दायित्व सौंपे जाने की खबरें आईं। सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों का तर्क (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बेअसर रहा भारत बंद

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। गुरुवार को सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों द्वारा दिए गए भारत बंद के एक दिवसीय आ 1 न का सामान्य जनजीवन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा।

कांग्रेस ने इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन किया। राहुल गांधी और

- भारत बंद से अधिकांशतः जनजीवन सामान्य रहा, लेकिन तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, गोवा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व पंजाब में मिलाजुला असर दिखा।

मल्लिकार्जुन खड़गे ने व्यापार समझौते और श्रम कानूनों को लेकर केन्द्र सरकार पर हमला बोला। खड़गे ने कहा कि देश (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘दूषित फल-सब्जियों की जांच के लिए 44 जिलों में मात्र 11 फूड सेफ्टी प्रयोगशालाएं ही क्यों हैं?’

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि हर जिले में फूड सेफ्टी लैब हो, ताकि लोगों को दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़े

-कार्यालय संवाददाता-
जयपुर, 12 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट व दूषित पानी में उगाई गई फल-सब्जियों से आमजन को होने वाली गंभीर बीमारियों के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश के 44 जिलों में मात्र 11 फूड सेफ्टी प्रयोगशालाएं ही क्यों हैं? राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रदेश के हर जिले में एक प्रयोगशाला हो और वहां पर्याप्त प्रशिक्षित अधिकारी हों, जो नहरों व सिंचाई के अन्य स्त्रों की जांच करके यह सुनिश्चित करें कि गंदे पानी व दवाइयों अथवा रसायनों के उपयोग से फल-सब्जियों की पैदावार नहीं की जाए। हाईकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल को इस प्रकरण में पक्षकार बनाया है। अदालत ने अलग-

अलग डेयरियों में दूध के सैंपल फेल होने के प्रकरण को भी गंभीरता से लेते हुए आरसीडीएफ को पक्षकार बनाने हुए जवाब तलब किया है कि दूध एकत्र करने के बाद प्लांट में पैकिंग तक, वह जांच की किन प्रक्रियाओं से गुजरता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश एस.पी.शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इसमें पूर्व महाधिवक्ता एम.एस. सिंघवी व उनके सहायक अधिवक्ता दर्श पारीक ने अदालत को बताया कि प्रदेश में कई जगहों पर फल-सब्जियों को उगाने में फैक्ट्रियों तथा सीवरेज व गंदे नालों के दूषित पानी का उपयोग किया जाता है। न्यायमित्र सिंघवी ने कहा कि जयपुर के लोग चौमूं की सब्जियां पसंद करते हैं,

- अदालत ने आदेश दिए कि जिन नदी-नालों का पानी सिंचाई के काम में लिया जा रहा है, वहां एस.टी.पी. और आरओ प्लांट लगाया जाए।
- हाईकोर्ट ने प्रदेश में कई डेयरी ब्रॉंड्स के दूध सैंपल फेल होने पर चिंता जताते हुए आरसीडीएफ से मिलावट रोकने तथा जांच की प्रक्रिया के बारे में पूछा।

लेकिन सांगानेर की नहीं, क्योंकि सांगानेर की जमीन में फैक्ट्रियों का दूषित पानी जा रहा है और यहां पैदा होने वाली सब्जियां इससे दूषित हो गई हैं। उन्होंने अदालत को अवगत करवाया कि कुछ समय पहले द्रव्यवती नदी के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) बंद हो गए थे और उसी गंदे पानी से फल-सब्जियां उगाई जा रही हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए न तो उपयुक्त

संख्या में लैब है और न ही अधिकारी। इस पर महाधिवक्ता ने जवाब दिया कि सांगानेर में एसटीपी संचालन करने वाली फर्म ने काम बीच में बंद कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू की है, वर्तमान में यह एसटीपी सुचारु रूप से चल रहा है। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता एम.एस. सिंघवी ने अदालत को बताया कि प्रदेश में 44 जिले हैं, लेकिन मात्र 11 ही

टैस्टिंग लैब हैं, यानी 4 जिलों पर केवल एक लैब है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उपयुक्त अधिकारी भी नहीं हैं, जो नालों के पानी की जांच के लिए प्रशिक्षित हों। इस पर महाधिवक्ता ने कहा कि टैस्टिंग लैब में अधिकारी नियुक्त करने के लिए भर्ती प्रक्रिया अदालती आदेशों के कारण लंबित थी, परंतु राज्य सरकार ने नई भर्तियां शुरू कर दी हैं। सुनवाई के दौरान यह दृश्य भी सामने आया कि नालों के पानी को ट्रीट करने के लिए एस.टी.पी. के साथ-साथ आरओ प्लांट भी लगाया जाए, परंतु प्रदेश के किसी भी जिले में एसटीपी के साथ आर.ओ. नहीं लगाया गया है। खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए महाधिवक्ता से कहा कि 11 प्रयोगशालाओं से प्रदेश के सभी जिलों में कैसे काम चलेगा। आप यह अपेक्षा

करते हैं कि एक जिले का आदमी जांच के लिए दूसरे जिले में जाएगा। राज्य सरकार को देखना चाहिए कि हर जिले में प्रयोगशाला हो, वह लोगों के नजदीक हो, ताकि उसका उपयोग हो सके। इस पर एजी ने कहा कि यह प्रशासनिक निर्णय है। अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के आयुक्त यह सुनिश्चित करें कि जिन नालों का पानी सिंचाई के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, वहां पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ-साथ आरओ प्लांट लगाया हुआ हो।

सोशल मीडिया पर मंदर डेयरी, अमूल और कंटी डिलिट्ट जैसे ब्रांड्स के दूध पैकेट्स के सैंपल जांच में फेल होने की जो खबरें चल रही हैं, वह मुद्दा भी सुनवाई के दौरान सामने आया। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कक्षा-10 की परीक्षा का फॉर्मेट बदला

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 फरवरी। विद्यार्थियों को सलाह दी गई है कि वे संशोधित प्रश्नपत्र पैटर्न से परिचित होने के लिए सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकण्डरी

- सीबीएसई ने विद्यार्थियों को सलाह दी है कि नए फॉर्मेट को समझने के लिए सीबीएसई की वैंबसाइट पर उपलब्ध विज्ञान व सामाजिक ज्ञान के नमूना प्रश्न पत्र को हल करें।

एजुकेशन (सीबीएसई) की शैक्षणिक वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के नमूना प्रश्नपत्रों का अध्ययन करें।

सीबीएसई ने कक्षा 10 की बोर्ड (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिएं। –रोबिन शर्मा

दस पिल्लरों के मजबूत आधार से लिखी जा रही 2047 के राजस्थान की इबारत

वैसे तो यह परंपरा रही है कि किसी भी सरकार का बजट हो और कितना ही विजनरी बजट हो पर सत्ता पक्ष उसके गुणगाण में लगता है तो विपक्ष कमियाँ ही कमियाँ देखने में जुट जाता है। इसलिए विल्टमेंप्री दिया कुमारी के 2 घंटे 54 मिनट के 143 पेज के बजट को लेकर आलोचना-प्रत्यालोचना से अलग हटकर देखना ही सही मायने में उसके साथ न्याय हो सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के तीसरे बजट में खास बात यह है कि यह बजट दूरगामी सोच यानी कि 2047 की राजस्थान की इबारत लिखने का बढ़ता कदम है। इस बजट को विजनरी बजट इस मायने में कहा जा सकता है कि पहली बार किसी बजट को समग्रता से रखा गया है। भजनलाल सरकार ने बजट को प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से दस पिल्लरों का ठोस आधार दिया है। इसे यों भी समझा जा सकता है कि प्रदेश के विकास के दस पिल्लरों से 2047 के राजस्थान का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। पिल्लर्स भी इस तरह से तैयार किये गये हैं जिससे किसी तरह के संदेह की गुंजाइस नहीं रह जाती है। आधारभूत संरचना से लेकर 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी का रोडमैप इस बजट में देखा जा सकता है।

राजस्थान की सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट को 10 पिल्लरों का आधार दिया है। वैसे तो सभी दस पिल्लर्स अपने आपमें अपना महत्व रखते हैं पर जिस तरह से इन पिल्लरों को प्राथमिकता दी गई है उससे यह साफ हो गया है कि प्रदेश के विकास का सशक्त आधार तय करने पर जोर दिया गया है। बजट में पहला पिल्लर इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार का है तो अन्य पिल्लरों में क्रमशः नागरिक सुविधाओं में गुणात्मक जीवन स्तर में सुधार, औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन, मानव संसाधन सशक्तिकरण, सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, पर्यटन, कला सांस्कृतिक धरोहर, सुशासन-डिजिटल परिवर्तन, कृषि विकास-किसान कल्याण, हरित विकास-पर्यावरण सततता और आखिरी व 10 वां पिल्लर 2047 का राजस्थान का है। देखा जाएं तो यह सभी दसों पिल्लर राजस्थान और राजस्थानवासियों के समग्र विकास और प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से गति देने वाले होने के साथ ही विकसित राजस्थान, शिक्षित राजस्थान, निरोगी राजस्थान, समृद्ध किसान-और खेती, औद्योगिक विकास, रोजगार और स्वरोजगार के विपुल अवसर, खनन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता की दर्शाता है। खास बात यह है कि प्रदेश के बजट में अरावली संरक्षण के प्रति दर्द भी है तो संरक्षण के प्रति गंभीरता भी स्पष्टता दिखाई देती है।

देखा जाएं तो यह सभी दसों पिल्लर राजस्थान और राजस्थानवासियों के समग्र विकास और प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से गति देने वाले होने के साथ ही विकसित राजस्थान, शिक्षित राजस्थान, निरोगी राजस्थान, समृद्ध किसान-और खेती, औद्योगिक विकास, रोजगार और स्वरोजगार के विपुल अवसर, खनन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। खासबात यह है कि प्रदेश के बजट में अरावली संरक्षण के प्रति दर्द भी है तो संरक्षण के प्रति गंभीरता भी स्पष्टता दिखाई देती है।

आधारभूत सुविधाएं और बेहतर कानून व्यवस्था किसी भी देश या प्रदेश में निर्बाध उपलब्ध होती है तो विकास की राह अपने आप खुलने लगती है। देशी-विदेशी निवेश आने लगता है तो औद्योगिक विकास से रोजगार और आय के साधन विकसित होते हैं। सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और इससे इकोनोमी को बूस्ट मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि जब समग्र विकास की रूपरेखा बनती है तो फिर निवासियों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक बदलाव आता ही है।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजनरी सोच को इस तरह से समझा जा सकता है कि सरकार के पहले साल में ही राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर औद्योगिक निवेश के करार किये गये। उसके बाद लगातार मोनेटरिंग का परिणाम है कि ग्राउण्ड ब्रेकिंग के प्रयासों में तेजी आई है। इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों को मातृभूमि से जोड़ने की जो पहल प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन से की है और अब प्रतिवर्ष इसके आयोजन का निर्णय किया है इसके भी सकारात्मक प्रयास आने ही हैं। क्योंकि प्रवासी राजस्थानियों ने अपने उद्यम कौशल से देश-दुनिया में डंका बजा रखा है और अब सरकार की पहल से इसका लाभ प्रदेश को मिलना ही है। क्योंकि प्रवासी राजस्थानी राजस्थान में आधारभूत सुविधाओं और निवेश अनुकूल माहौल से भरित होकर प्रदेश में निवेश के लिए आगे आयेगी ही और इसका एक बड़ा कारण सरकार का प्रोएक्टिव रोल व दूसरा सरकार द्वारा प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़ने की भावनात्मक पहल है।

सवाल यह नहीं है कि किस क्षेत्र के लिए कितना बजट दिया गया है या किस क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दी गई है अपितु यह है कि समग्र रूप से दसों पिल्लर अपने-अपने क्षेत्रों में परफरमेंस दिखाते हैं तो 2047 की सशक्त इमारत तैयार होने से कोई नहीं रोक सकता। राज्य के बजट को इस दृष्टि से भी देखने की आवश्यकता है।

–अतिथि सम्पादक, डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा (वरिष्ठ लेखक)



पंडित अनिल शर्मा

राशिफल शुक्रवार 13 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, मूल नक्षत्र सायं 4:16 तक, वज्र योग रात्रि 3:23 तक, बालव करण दिन 2:26 तक, चन्द्रमा आज धनु राशि में संचार करेगा।

गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-धनु, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरू-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह कुमार योग सूर्योदय से दिन 2:26 तक है। राजयोग सायं 4:13 से सूर्योदय तक है। आज विजया एकादशी व्रत, संक्रांति पुण्य काल पूर्वान्ह में है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:32 तक, लाभ-अमृत 8:32 से 11:18 तक, शुभ 12:41 से 2:04 तक, चर 4:50 से सूर्यास्त तक।

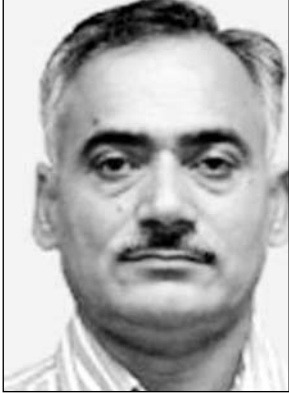
राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:09, सूर्यास्त 6:13

 मेघ नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटके हुए कार्य बने लगेंगे। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।	 सिंह व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों को उचित सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 धनु व्यावसायिक कार्यों से संबंधित प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।
 वृष चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब होने का भय रहेगा। आज बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।	 कन्या घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 मकर घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज समय अनलल कार्यों में खराब होगा। मन में असंतोष बना रहेगा।
 मिथुन परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।	 तुला व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।	 कुंभ आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। वृद्धि होगी। संभावित खोस से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।
 कर्क व्यक्तिगत परेशानियों से राहत मिलेगी। अनहोनी की आशंका से बचा हुआ मन का भय दूर होगा। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है।	 वृश्चिक व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगें। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 मीन व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेगें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

संपादकीय

राजस्थान बजट 2026-27 : सुदृढ़ कानून व्यवस्था से समृद्धि

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट सुरक्षा और समृद्धि के संतुलित समन्वय का दस्तावेज है



ओ. पी. गल्होत्रा

राजस्थान का बजट 2026-27 विकास की रूपरेखा होने के साथ ही सुरक्षित और विश्वासपूर्ण समाज के निर्माण का भी स्पष्ट संकल्प है। किसी भी राज्य की प्रगति का वास्तविक आधार उसकी कानून-व्यवस्था होती है। यदि नागरिक स्वयं को सुरक्षित महसूस करें, निवेशक निश्चित होकर पूंजी लाएँ, महिलाएँ और बच्चे भयमुक्त वातावरण में जीवन जी सकें, तभी विकास के सभी आंकड़े सार्थक सिद्ध होते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट सुरक्षा और समृद्धि के संतुलित समन्वय का दस्तावेज है। कुल 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपये के आकार वाला यह बजट न केवल आर्थिक विस्तार की दर्शाता है, बल्कि प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र

के सुदृढ़ीकरण की स्पष्ट दिशा भी देता है। बजट में किए गए प्रावधान प्रदेश में कानून-व्यवस्था को आधुनिक, जवाबदेह और तकनीक-सक्षम बनाने की व्यापक योजना प्रस्तुत करते हैं। बजट में पुलिस बल की संरचनात्मक मजबूती पर जोर दिया गया है। रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती और प्रशिक्षण व्यवस्था के आधुनिकीकरण का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। लंबे समय से पुलिस बल पर बढ़ते कार्यभार को देखते हुए यह आवश्यक था कि बल की संख्या और क्षमता दोनों में वृद्धि हो। नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति से थानों में लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण होगा और गश्त व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। इससे अपराध की रोकथाम में प्रत्यक्ष सुधार देखने को मिलेगा।

डिजिटल युग में अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। साइबर अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल ठगी जैसे मामलों में वृद्धि के परिप्रेष्य में प्रत्येक संभाग में अत्याधुनिक साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना का निर्णय दूरदर्शी कदम है। इससे न केवल अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में तेजी आएगी, बल्कि आम नागरिकों में डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी।यह पहल दर्शाती है कि सरकार भविष्य की चुनौतियों के लिए वर्तमान में तैयारी कर रही है।

महिला सुरक्षा इस बजट की प्राथमिकताओं में स्पष्ट रूप से

परिलक्षित होती है। प्रत्येक जिले में महिला सहायता डेस्क और विशेष अन्वेषण प्रकोष्ठ की स्थापना से पीड़ित महिलाओं को त्वरित और संवेदनशील सहायता मिलेगी। महिला अपराधों की जांच के लिए समयबद्ध प्रणाली और फास्ट ट्रैक दृष्टिकोण से न्याय की प्रक्रिया में गति आएगी। यह संदेश भी जाएगा कि राज्य सरकार महिला सुरक्षा के प्रश्न पर किसी प्रकार की हिलाई बरतने के पक्ष में नहीं है।

पुलिस थानों के आधुनिकीकरण और डिजिटल केस मैनेजमेंट प्रणाली का विस्तार कानून-व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सीसीटीवीएनएस के उच्चम और डेटा इंटीग्रेशन से अपराधियों का ट्रैक रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध होगा, जिससे अपराधनियंत्रण की प्रक्रिया अधिक सटीक और त्वरित बनेगी। संवेदनशील क्षेत्रों में स्मार्ट सर्बिलॉस और सीसीटीवी नेटवर्क का विस्तार सार्वजनिक स्थलों पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करेगा, जिससे अपराध की संभावनाएँ स्वतः कम होंगी। समुदायिक पुलिसिंग को प्रोत्साहन देने का निर्णय भी उल्लेखनीय है। कानून-व्यवस्था केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना का परिणाम होती है। नागरिकों और पुलिस के बीच संवाद को मजबूत कर विश्वास का वातावरण बनाया जा सकता है। समुदायिक सहभागिता से स्थानीय स्तर पर विवादों का समाधान शीघ्र

होगा और असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगेगा।

पुलिस कमियों के आवास, कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य सहायता कार्यक्रमों के लिए विशेष प्रावधान भी इस बजट की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। निरंतर दबाव में कार्य करने वाले पुलिस बल के मनोबल को बनाए रखना उतना ही आवश्यक है जितना कि तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराना। जब बल संतुष्ट और प्रेरित होगा, तो उसका प्रदर्शन भी बेहतर होगा। इन सभी पहलों का परिणाम प्रदेश की समग्र कानून-व्यवस्था की स्थिति में स्पष्ट सुधार के रूप में सामने आया है। संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और महिला अपराधों के मामलों में सख्त कार्रवाई से अपराधियों में भय और नागरिकों में विश्वास का वातावरण बना है। निवेशकों के लिए सुरक्षित माहौल उपलब्ध होने से औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ी हैं और पर्यटन क्षेत्र में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

विकास और सुरक्षा परस्पर पूरक हैं। जब राज्य की सकल घरेलू उत्पाद 21 लाख 52 हजार करोड़ रुपये से अधिक पहुँचने का अनुमान हो, प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो, शिक्षा और स्वास्थ्य पर रिकॉर्ड निवेश हो, तो यह सब तभी सार्थक है जब समाज सुरक्षित हो। 53 हजार 978 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय, शिक्षा के लिए 69 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान और स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़े

निवेश भी अंततः उसी सामाजिक स्थिरता पर निर्भर करते हैं, जिसकी नींव मजबूत कानून-व्यवस्था से पड़ती है।

कृषि, जल प्रबंधन और महिला सशक्तिकरण जैसी योजनाएँ सामाजिक असमानताओं को कम करती हैं और इससे अपराध के सामाजिक कारणों में कमी आती है। युवाओं को रोजगार के अवसर, पारदर्शी भर्ती प्रणाली और कौशल विकास कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देते हैं। इस प्रकार यह बजट अपराध नियंत्रण को केवल दंडात्मक दृष्टि से नहीं, बल्कि संरचनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखता है। समग्र रूप से राजस्थान बजट 2026-27 यह स्पष्ट संदेश देता है कि सरकार विकास को सुरक्षा से अलग नहीं मानती। आधुनिक पुलिसिंग, तकनीकी सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, सामुदायिक सहभागिता और पुलिस कल्याण आदि सभी आयामों के माध्यम से प्रदेश में एक सुरक्षित, स्थिर और निवेश-अनुकूल वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया गया है।

इन घोषणाओं के समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन से राजस्थान न केवल आर्थिक प्रगति के मानकों पर, बल्कि कानून-व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में भी देश के अटाणी राज्यों में स्थान प्राप्त करेगा।

–ओ. पी. गल्होत्रा, महानिदेशक पुलिस (सेनि.)

समृद्ध राजस्थान की ओर निर्णायक कदम है प्रदेश का बजट



सीए सुनील भागंव

राजस्थान का बजट 2026-27 आय-व्यय का औपचारिक दस्तावेज होने के साथ ही राज्य की विकास-दृष्टि का सुसंगठित घोषणापत्र है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री श्रीमती दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत यह बजट स्पष्ट संकेत देता है कि सरकार अल्पकालिक लोकलुभावन उपायों के बजाय दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से समृद्ध प्रदेश के संकल्प को साकार करना चाहती है। लगभग 6.11 लाख करोड़ रुपये के बजट आकार के साथ यह वित्तीय खाका विकास, सुशासन और सामाजिक संतुलन पर आधारित है। राजकोषीय प्रबंधन की दृष्टि से यह उल्लेखनीय है कि सरकार ने विकास व्यय में वृद्धि करते हुए भी वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है। राजकोषीय घाटे (79 हजार करोड़ से अधिक) का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का

3.69 प्रतिशत रहना यह दर्शाता है कि सरकार ने जिम्मेदार वित्तीय नीति को प्राथमिकता दी है। अनुमानित 21.52 लाख करोड़ रुपये का सकल घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के विस्तार की संभावनाओं को रेखांकित करता है।

किसी भी राज्य की समृद्धि का आधार उसका आधारभूत ढांचा होता है। बजट में सड़कों, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज, बाईपास और राज्य राजमार्गों के विस्तार एवं उन्नयन के लिए 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह निर्माण कार्य आर्थिक गतिविधियों की गति बढ़ाने की रणनीति है। क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए 1400 करोड़, अटल प्रगति पथ के लिए 500 करोड़ एवं राज्य राजमार्ग के लिए 2700 करोड़ से सड़कों की स्थिति बेहतर होगी। इंटरलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना और प्रमुख मार्गों पर आधुनिक निगरानी तंत्र का विस्तार शहरीकरण की चुनौतियों का तकनीकी समाधान प्रस्तुत करता है। इससे सड़क सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और पारदर्शिता में सुधार होगा।

पेयजल क्षेत्र में मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) के विस्तार और 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव राज्य की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। बीसलपुर परियोजना से जलापूर्ति सुदृढ़ करने के लिए नई ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण दीर्घकालिक जल सुरक्षा का संकेत है। ऊर्जा क्षेत्र में 4,830 मेगावाट क्षमता के सौर पार्कों के विकास को योजना

राजस्थान को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह हरित विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता का संतुलित मॉडल प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ सुविधा, लॉजिस्टिक हब और इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना जैसे कदम उठाकर निवेश वातावरण को सुदृढ़ करने का संकेत दिया है। ~2024 के तहत मैनुफैक्चरिंग के साथ सेवा क्षेत्र को भी प्रोत्साहन देना औद्योगिक विस्तार की स्पष्ट दृष्टि को दर्शाता है। सरकार ने वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य तभी संभव है जब निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को समानांतर गति दी जाए और बजट में इन तीनों आयामों को स्पष्ट रूप से संबोधित किया गया है।

समृद्ध प्रदेश की परिकल्पना युवाओं की सहभागिता के बिना अधूरी है। चार लाख भर्तियों के संकल्प को दिशा में एक लाख से अधिक नियुक्तियाँ और निजी क्षेत्र में दो लाख से अधिक रोजगार सृजन का उल्लेख राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्तमान में 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन होना प्रशासनिक सक्रियता का संकेत है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रेरित करेगा। शिक्षा क्षेत्र में 400 विद्यालयों को – स्कूलों

में उन्नत करने हेतु 1,000 करोड़ रुपये का निवेश गुणवत्ता सुधार का ठोस प्रयास है। आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब्स और डिजिटल मेंटरिंग कार्यक्रम यह संकेत देते हैं कि सरकार शिक्षा को तकनीकी नवाचार से जोड़कर भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना चाहती है।

स्वास्थ्य क्षेत्र में आधुनिक विश्राम गुहों और जेके लॉन हॉस्पिटल में 500 बेड के टॉवर के निर्माण हेतु बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्तावित है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए – कार्यक्रम और जिला स्तर पर मेंटल हेल्थ केयर सेल की स्थापना यह दर्शाती है कि सरकार स्वास्थ्य को केवल शारीरिक उपचार तक सीमित नहीं मानती। महिलाओं के लिए ऋण सीमा में वृद्धि, ‘नंद घर’ मॉडल की आंगनबाड़ियों का विस्तार और लक्षप्रति दीदी योजना सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में ठोस कदम हैं।

कृषि क्षेत्र में 11,300 करोड़ रुपये से अधिक की सिंचाई परियोजनाएँ और 50 हजार सौर पंप संयंत्रों की योजना किसान हितैषी दृष्टिकोण के रेखांकित करती है। 35 लाख से अधिक किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के व्याज मुक्त फसली ऋण का प्रावधान ठागीम अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा। राज मिशन के माध्यम से कृषि उत्पादों को वैश्विक पट्टाचन दिलाने का प्रयास कृषि के मूल्य संवर्धन और निर्यात से जोड़ता है।

‘हरियालो-राजस्थान’ के अंतर्गत

10 करोड़ पौधा रोपण का लक्ष्य पर्यावरणीय प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जल संरक्षण के लिए 2.0 के तहत व्यापक निवेश और वन्यजीव संरक्षण हेतु परियोजना हरित विकास की व्यापक सोच को दर्शाती है। कार्बन क्रेडिट पायलट परियोजना और औद्योगिक अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए निर्माण यह संकेत देते हैं कि औद्योगिक विकास को पर्यावरणीय संतुलन के साथ जोड़ा गया है।

व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म पर 100 सेवाओं की शुरुआत, मिनी ई-मिच मॉडल और – जैसी पहलें प्रशासन को पारदर्शी, उत्तरदायी और डेटा-आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। बजट 2026-27 एक समग्र विकास दृष्टि प्रस्तुत करता है जिसमें अवसंरचना, उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के बीच संतुलित तालमेल दिखाई देता है।

इस बजट से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार केवल घोषणाएँ नहीं, बल्कि परिणामोन्मुख नीतिगत ढाँचा स्थापित करना चाहती है। यदि प्रस्तावित योजनाओं का समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ, तो यह बजट राजस्थान को आर्थिक मजबूती के साथ सामाजिक समृद्धि की नई ऊँचाइयों तक ले जा सकता है। समृद्ध प्रदेश का संकल्प अब नीतिगत दस्तावेज में रूपान्तरित हो चुका है, अब परीक्षा उसके प्रभावी क्रियान्वयन की है।

–सीए सुनील भागंव, आर्थिक मामलों के जानकार

राजस्थान बजट 2026-27 : विकास की नई ऊंचाइयां और वित्तीय मजबूती का प्रमाण



डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत

राजस्थान सरकार ने 2026-27 के लिए 6.11 लाख करोड़ रुपये (लगभग 6 लाख 10 हजार 956 करोड़) का बजट पेश किया है, जो पिछले बजट की तुलना में 42 प्रतिशत की अप्रत्याशित उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत इस बजट में राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार तेजी से बढ़ने का प्रमाण मिलता है-41.39 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अब यह 21.52 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचने का अनुमान है। प्रति

व्यक्ति आय 1.67 लाख से बढ़कर 2.02 लाख रुपये हो गई है, जो सरकार ने इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर राज्य को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थान दिलाया है। पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) इस बजट की सबसे मजबूत विशेषता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सर्वाधिक आवंटन किया गया है-सड़कों, पुलों, जल आपूर्ति और सौर ऊर्जा पर फोकसा उदाहरणस्वरूप, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नल जल पहुँचाने के लिए 6,800 करोड़ रुपये, बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क्स के लिए 3,000 करोड़ रुपये (विशेष रूप से 2,950 करोड़ का प्रावधान), और कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3,427 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। 42,000 किमी नई सड़कों का निर्माण, 6,500 गांवों में जल कनेक्शन, सिनल-ग्रीं शहर, पीपम आवास योजना का विस्तार, और डूनेज-सड़क लाइट जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

केंद्र सरकार के 12.2 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स से प्रेरित होकर राजस्थान भी इंफ्रास्ट्रक्चर-

प्रतिशत और 46 प्रतिशत के आसपास है। सरकार ने इन क्षेत्रों में निवेश बढ़ाकर राज्य को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मजबूत स्थान दिलाया है।

पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) इस बजट की सबसे मजबूत विशेषता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सर्वाधिक आवंटन किया गया है-सड़कों, पुलों, जल आपूर्ति और सौर ऊर्जा पर फोकसा उदाहरणस्वरूप, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नल जल पहुँचाने के लिए 6,800 करोड़ रुपये, बीकानेर और जैसलमेर में नए सोलर पार्क्स के लिए 3,000 करोड़ रुपये (विशेष रूप से 2,950 करोड़ का प्रावधान), और कुल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 3,427 करोड़ रुपये का प्रस्ताव। 42,000 किमी नई सड़कों का निर्माण, 6,500 गांवों में जल कनेक्शन, सिनल-ग्रीं शहर, पीपम आवास योजना का विस्तार, और डूनेज-सड़क लाइट जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

केंद्र सरकार के 12.2 लाख करोड़ रुपये के कैपेक्स से प्रेरित होकर राजस्थान भी इंफ्रास्ट्रक्चर-

लेड ग्रोथ को प्राथमिकता दे रहा है। इससे रोजगार सृजन होगा, निवेश आकर्षित होगा, और राज्य की आर्थिक क्षमता मजबूत होगी।

अर्थव्यवस्था के आकार में वृद्धि और कैपेक्स बढ़ोतरी से राज्य की समग्र प्रगति स्पष्ट है। राइजिंग राजस्थान माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश आकर्षित हुए, जिनमें से 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स बाउंड पर हैं। यह डबल इंजन सरकार की सफलता है। कृषि क्षेत्र में 25,000 करोड़ रुपये के व्याज-मुक्त ऋण, युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना में 30,000 युवाओं को 10 लाख तक व्याज-मुक्त लोन, 400 इनोवेटिव स्कूल, होमगार्ड में 5,000 नए पद, और फ्री इलाज जैसी योजनाएँ आमजन की सेवा में सरकार की प्रतिबद्धता दिखाती हैं। एमएफएमई, पर्यटन, और रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस से राज्य को ऊर्जा सुरक्षा और रोजगार का हब बनाया जा रहा है।

फिस्कल डिस्प्लिन बनाए रखते हुए यह विकास संभव हुआ है। राजस्व प्राप्तियाँ मजबूत हुई हैं-केंद्रीय करों

से 90,445 करोड़ रुपये प्राप्त। विकास घाटा और फिस्कल घाटा नियंत्रित स्थिति में हैं, जबकि कैपेक्स बढ़ रहा है। पिछले वर्षों में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 1.6-1.9 प्रतिशत रहा, जो बेहतर प्रबंधन दर्शाता है। सरकार ने उद्योग को उत्पादक उपयोग में लगाया, जिससे भविष्य में व्याज बोझ कम होगा और विकास डिफेंस बनेगा।

यह बजट युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए आशा की किरण है। 100 से अधिक योजनाएँ, रोजगार सृजन, पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास को मॉडल पेश करता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सिद्धांत पर चल रही है। यह बजट राजस्थान को विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से ले जाएगा और 2029 में राज्य की 350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की तत्पर तेज कदम होगा।

लेखक राजस्थान भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं।

- डॉ. सुरेंद्रसिंह शेखावत

दुर्लभ बीमारी का सफल उपचार

उदयपुर, (कासं)। पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, मिस्र, उमरडा, उदयपुर के श्वसन रोग विभाग में एक अत्यंत दुर्लभ एवं जटिल चिकित्सकीय प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। संस्थान के चेयरमेन आशीष अग्रवाल ने बताया कि 66 वर्षीय पुरुष मरीज सांस फूलने तथा खांसी से साथ खून आने (हीमोप्टाइसिस) की शिकायत के साथ श्वसन रोग विभाग में भर्ती हुआ। मरीज की प्रारंभिक जांच के

अंतर्गत छाती का एक्स-रे एवं एचआरसीटी थोरैक्स किया गया, जिसमें असामान्य निष्कर्ष सामने आए। आगे की विस्तृत जांच के लिए ऑंकोरकोपी की गई, जिसमें दाहिने फेफड़े के राइट मिडल लोब में एक कठोर, पथरी जैसी संरचना पाई गई, जिसे चिकित्सकीय भाषा में ब्रोकोलिथ कहा जाता है। इस दुर्लभ ब्रोकोलिथ को अत्यंत सावधानीपूर्वक डारमिया बास्केट की सहायता से सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया।

कार्यालय ग्राम पंचायत लकड़वास, पंचायत समिति गिर्वा, जिला-उदयपुर

क्रमांक: निविदा/2025-26/60 दिनांक:- 10.2.2026

:- खुली निविदा सूचना- 04-05/2025-26 :-

कार्यालय ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्वीकृत कार्यों हेतु खुली-निविदाएं आमंत्रित कि जाती है अत: उक्त कार्य हेतु इच्छुक संवेदको/फर्मों से ऑनलाईन ई-निविदाएं दिनांक:- 17.02.2026 को प्रात:- 11.00 बजे तक ऑनलाईन ई-प्रोक्योमेंट पोर्टल पर आमंत्रित की जाती है।विस्तृ विवरण/जानकारीsppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajathan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN No ZUD2526WSOB04498	
ZUD2526WSOB04499	
प्रशासक	ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत-लकड़वास	ग्राम पंचायत-लकड़वास
पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर	पं.स. गिर्वा, जिला-उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर (राज) वाद पदों के स्थिरिकरण के लिए प्रतिवादी को सम्मन (आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता) पत्रावली संख्या: 142/25 (विविध) श्री किशनलाल बनाम श्री दौला

वास्ते,

- श्री रमेशियापिता पन्ना भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- मांगी पिता पन्ना भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- नाजी पिता पन्ना भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- चन्दरी पिता भंवर भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- गेन्दी पिता पंररा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- सायरीबाई पिता जीता भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- गुलाबीबाई पिता लोगर भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- छायाबाई पिता लोगर भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- प्यारीबाई पिता लोगर भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- हुडीबाई पिता लोगर भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री चेना पिता लखुडा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री गुरु पिता मेघा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- सीता पिता मेघा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- देवली पिता हीरा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री रूप पिता भीरा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री राजु पिता मेघा भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री गोकल पिता भाग्य भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री पेमा पिता भाता भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री कैलास पिता प्यार भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- लोरीर पिता प्यार भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- प्रेमी पिता प्यार भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री मींदुलाल पिता देवली भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री कालुलाल पिता देवली भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री बाबुलाल पिता देवली भील, निवासी मोटीखेडी, तहसील भासा, जिला उदयपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 R.A.अ.

चुकि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरुद्ध के लिए एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 पू. रा.अ. के तहत पेश किया। अत: आप सभी विपक्षीगण को एतद् द्वारा आहूत किया जाता है कि आप या तो स्वयं या तो ऐसे अधिकाधिक को सम्यकरूपण अनुदिष्ट हो व प्रार्थना पत्र सम्बन्धी सर्व सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो या जिसके साथ ऐसा कोई हो जो ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो के द्वारादिनांक 27.02.2026 को समय 10.00 बजे प्रात: दावे का उत्तर देने हेतु इस न्यायालय में उपस्थित हो।

सुचित रहे कि पूर्णवर्षित दिवस का आपके द्वारा अपनी उपस्थिति में व्यक्तिकम होने पर कथित वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना व अवधारित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)

न्यायालय की मुहर

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर (राज) वाद पदों के स्थिरिकरण के लिए प्रतिवादी को सम्मन (आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता) पत्रावली संख्या: 01/26 (वाद) श्री प्रेमानन्द बनाम श्रीमती ईन्द्रा

वास्ते,

- कमला पुत्री कालु धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्रीमती केसी पत्नी हीरा धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री हेमराज पुत्र केसी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री भुरालाल पुत्र केसी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- प्रेम पुत्री केसी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- गीता पुत्री केसी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री नन्दलाल पुत्र गुलाबी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री माधुलाल पुत्र गुलाबी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- रुकमणी पुत्री गुलाबी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- किशोरी पुत्री गुलाबी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- सोमर पुत्री गुलाबी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- सोधा पुत्री गुलाबी धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- गोपी पुत्री प्रधा धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री पंकर पुत्र जम्ना धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री सुमिल पुत्र जम्ना धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री कैलास पुत्र जम्ना धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- देऊ पुत्री कनीबाई धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री देवेन्द्र पुत्र मोहनलाल धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री धनपाल पुत्र नारायण धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री झमकलाल पुत्र नारायण धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री नारायण पुत्र नारायण धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- वसन्ती पुत्री नारायण धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- हुडी पुत्री नारायण धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री भुपरा पुत्र प्रधा धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री मोती पुत्र नाथु धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री मोहनलाल पुत्र गणपत धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- रेखा पुत्री मोहनलाल धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री रतनलाल पुत्र कनीबाई धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री तम्रे पुत्र हीरा धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- रीना पुत्री मोहनलाल धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- तेरी पुत्री प्रधा धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री लालु पुत्र कनीबाई धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्री लालु पुत्र नाथु धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- लीला पुत्री कनीबाई धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
- श्रीमती लीलादेवी पत्नी मोहनलाल धोबी, निवासी ईण्टाली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

चुकि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध के लिए एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 के तहत पेश किया। अत: आप सभी प्रतिवादीगण को एतद् द्वारा आहूत किया गया जाता है कि आप या तो स्वयं ऐसे या अधिकाधिक को सम्यकरूपण अनुदिष्ट हो व वाद सम्बन्धी सर्व सारवान प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो या जिसके साथ ऐसा कोई हो जो ऐसे सब प्रश्नों के उत्तर देने में समर्थ हो के द्वारा दिनांक 05.03.2026 को समय 10.00 बजे प्रात: दावे का उत्तर देने हेतु इस न्यायालय में उपस्थित हो।

सुचित रहे कि पूर्णवर्षित दिवस का आपके द्वारा अपनी उपस्थिति में व्यक्तिकम होने पर कथित वाद आपकी अनुपस्थिति में सुना व अवधारित किया जावेगा।

आज दिनांक 10.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)

न्यायालय की मुहर

सहायक कलक्टर (FT) मावली

श्रमिक संगठनों का प्रदर्शन

उदयपुर/डूंगरपुर (कासं)। केंद्र सरकार की श्रम और आर्थिक नीतियों के विरोध में गुरुवार को देशभर में आहुत राष्ट्र व्यापी श्रमिक हड़ताल का असर उदयपुर में भी देखने को मिला। विभिन्न श्रमिक संगठनों, किसान संगठनों और कर्मचारी यूनियनों ने शहर में रैली निकालकर जिला कलेक्ट्री पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।

केंद्रीय श्रमिक संगठनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त अह्वान पर गुरुवार को आहुत राष्ट्रीय आम हड़ताल के तहत उदयपुर शहर में बैंक एबीमाएओद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों, महिला संगठनों,किसानों व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने टाउन हॉल से रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया एवं सभा का आयोजन किया। सभा की अध्यक्षता इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने की

रैली के दौरान मजदूर विरोधी श्रम कोड वापस ले,जी राम जी योजना रद्द करो,मनरेगा कानून को पुन: बहाल करो,निजीकरण ठेकाकरण नहीं चलेगा,सामाजिक सुरक्षा पर हमले बंद करो, बिजली संशोधन विधेयक 2025 वापस लेो आदि नारे लगाते हुए रैली जिला कलेक्ट्रेट पर पहुँच कर प्रदर्शन किया व इस के पश्चात सभा आयोजित की गई। इंटक के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार श्रमिकों व किसानों के खिलाफ नीतियां लेकर आ रही है। इस सरकार ने 29 मजदूर कानूनों को हटाकर चार मजदूर संहिताएं लेकर आई है जो दशकों से अर्जित श्रमिक अधिकारों को कमजोर करती है।एनौकीरी की सुरक्षा समाप्त होती है, हायर एंड फायर को वैध बनाया जा रहा है,सामुहिक सोदेबाजी व हड़ताल के अधिकार को कमजोर किया जा रहा है।

इन श्रम संहिताओं से ट्रेड यूनियन अधिकारों को कमजोर करने का इरादा है श्रम निरीक्षक व्यवस्था को निष्प्रभावी बनाते हैं ऐसे कानून को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए।

डूंगरपुर संवाददाता के अनुसार : मोदी सरकार द्वारा पहले मजदूर विरोधी लेबर कोड थोपने और अब गरीबों के रोजगार के अधिकार को खत्म करने के खिलाफ 12 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल में स्कीम वर्कर्स, मजदूर, किसान, कर्मचारी, संविदा कर्मियों ने बढ चढकर जिला कलेक्ट्री कार्यालय के बाहर भागीदारी की। सीटू के नेतृत्व मे विभिन्न जनसंगठन से जुडे कार्यकर्ता जिसमें आँगनवाडी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, कुक कम हेलपर, रिब्लिङ वर्कर मजदूर कृषक मित्र,किसान आदि पहले बादल महल रोड पर इकठ्ठा हुए।

एकीकृत कृषि प्रणाली माॅड्यूल का सजीव प्रदर्शन

उदयपुर, (कासं)। क्षेत्रीय कृषि मेला-2026 एवं फल-फूल-सब्जी प्रदर्शनी के अवसर पर महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के तत्वावधान में अखिल भारतीय समन्वित कृषि प्रणाली परियोजना द्वारा एकीकृत कृषि प्रणाली माॅड्यूल का सजीव प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शनी का अवलोकन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भारगीधर चौधरी, कुलगुरु महोदय डॉ. प्रताप सिंह, मानव संसाधन प्रबंधन के सहायक महानिदेशक डॉ.एस. के. शर्मा, प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. आर. एल.

सोनी, कुल सचिव श्री अशोक कुमार, डॉ. मनोज महाला, डीन, आरसीए, एमपीयूएटी, उदयपुर एवं ओएसडी डॉ सिद्धार्थ मिश्रा, द्वारा किया गया।

इस अवसर पर डॉ. हरि सिंह, प्रधान अन्वेषक ने एकीकृत कृषि प्रणाली माॅड्यूल की कार्यप्रणाली, इसके विभिन्न घटकों जैसे फसल उत्पादन, बागवानी, पशुपालन, मृगीपालन, मछली पालन, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन एवं संसाधन पुनर्चक्रण आदि के समन्वय के बारे में आगंतुकों एवं किसानों को विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि एकीकृत

कृषि प्रणाली अपनाने से एक हेक्टेयर क्षेत्र से 2.30 लाख रुपये तक की अतिरिक्त शुद्ध आय एवं 474 मानव-दिवस का रोजगार सृजित किया जा सकता है। इससे किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि, जोखिम में प्रभावी कमी तथा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम एवं सतत उपयोग संभव हो पाता है।

मेले के दौरान पाँच जिलों के 2000 से अधिक किसानों, कृषि वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों एवं अन्य आगंतुकों ने एकीकृत कृषि प्रणाली माॅड्यूल का अवलोकन किया।

‘गीतांजली पैथटॉक’ कल से ‘अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा बजट’

उदयपुर, (कासं)। गीतांजली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, उदयपुर के पैथोलॉजी विभाग द्वारा उदयपुर सोसायटी ऑफ पैथोलॉजिस्ट्स के सहयोग से 14 व 15 फरवरी को दो दिवसीय ‘गीतांजली अस्पटलक 2026’ जोनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ शनिवार को प्रातः 8.15 बजे होगा।

कॉन्फ्रेंस की थीम डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी में उभरते रुझान क्या नया है, क्या प्रारंभिक और आगे आगे

रखी जाएंगी। इस सम्मेलन में देश के प्रख्यात ऑनकोपैथोलॉजिस्ट्स एवं विशेषज्ञ चिकित्सक भाग लेंगे तथा राजस्थान और गुजरात सहित विभिन्न राज्यों से पैथोलॉजिस्ट, शोधकर्ता और मेडिकल विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे।

रजिस्ट्रेशन शिविर में 55 लाइसेंस हाथों-हाथ जारी

भीम, (निंस्)। कस्बे के सदर बाजार सिंधी धर्मशाला में बुधवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस में पंजीयन सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर शिविर आयोजित किया गया।

राजसमंद जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा ने बताया कि आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण डॉक्टर टी शुभ मंगला के निर्देशन में तथा मुख्य चिकित्साएं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत कुमार बिंदल के आदेशानुसार भीम में सदर बाजार स्थित सिंधी धर्मशाला में खाद्य लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित शिविर में विभिन्न खाद्य पदार्थ विक्रेताओं

के 55 रजिस्ट्रेशन तथा लाइसेंस मौके पर ही जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत सभी खाद्य विक्रेताओं को रजिस्ट्रेशन अथवा लाइसेंस लिया जाना आवश्यक था। बिना खाद्य अनुज्ञा पत्र के व्यापार करने वाले खाद्य व्यापारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा व्यापारियों को शुद्ध तथा गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री विक्रय करने हेतु निर्देशित किया गया एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। टीएम में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। टीएम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा, प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र डांगी तथा सहायक महेंद्र सिंह उपस्थित रहे।

जेवरत चोरी करने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के सूरजपोल थाना पुलिस ने बस में सवार महिला के पर्स से सोने के जेवरत चोरी करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार पीडिता जामुडा गोंगला सलून्बर हॉल बप्पारावल नगर हिरणगौी सेक्टर 6 निवासी प्रेमकंकर

पत्नी चन्द्रवीरसिंह चुण्डावत ने सूरजपोल पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया। जिसमें उसने बताया कि 9 फरवरी दोपहर में बस में बैठ कर सलून्बर जा रही थी। इस दौरान अज्ञात चोर मेरे पर्स से सोने की कड़े, मंगसूत, अंगुठी चुरा ले गया। इसका पता चलने

पर पुलिस को सूचना कर प्रकरण दर्ज करवाया। इस मामले में प्रकरण दर्ज होने पर अनुसंधान अधिकारी एसएसआई तेजसिंह ने मामले में मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी वणी भीण्डर निवासी सोहनलाल पुत्र गोरभन लौहार को गिरफ्तार कर रिमाण्ड पर लिया है।

जिला कलक्टर ने ग्रामीणों की सुनी परिवेदनाएं

उदयपुर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के सुशासन के संकल्प को सकार करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। इसी क्रम में जिला कलक्टर नमित मेहता ने बुधवार को भीण्डर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान ग्राम पंचायत वरणी में रात्रि चौपाल करते हुए जिला कलक्टर ने आमजन की परिवेदनाओं को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ सुना और त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इससे पूर्व उपखण्ड कार्यालय भीण्डर और पुलिस थाने का निरीक्षण किया।

जिला कलक्टर मेहता बुधवार देर

शाम ग्राम पंचायत वरणी पहुंचे। वहां जिला व उपखण्ड स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में रात्रि चौपाल हुई। चौपाल में पेयजल, सड़क, विद्युत, राजस्व प्रकरणों सहित विभिन्न विभागों से जुडी समस्याएं रखीं।

चौपाल में नवीन पुष्पचिकित्सा केंद्र स्वीकृत करने, पेयजल पाइपलाइन मरम्मत, सड़क, परम्परा, अतिक्रमण, पेयजल में फ्लोराइड समेत विविध प्रकरण प्राप्त हुए। जिला कलेक्टर ने जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो और ग्रामीणों को तत्काल राहत प्रदान की जाए। कलेक्टर

मेहता ने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान प्रशासन की सर्वाच्च प्राथमिकता है। उन्होंने ग्राम स्तर पर आवश्यक विकास कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र प्रतिक्रिया करने के निर्देश भी दिए, ताकि बजट प्रावधान के अनुसार कार्यों को स्वीकृति दिलाई जा सके। अधिकारियों ने मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान किया तथा शेष मामलों में निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बिरमाराम सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारियों समेत ग्रामीण मौजूद रहे।

 SRG HOUSING FINANCE LIMITED CIN: L65922RJ1989PLC015440 321, एच.एच. लोहा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री लॉकल के पास, उदयपुर – 313001 (राजस्थान) दूरभाष : 0294- 2412609, ईमेल: info@srghousing.com, वेबसाइट: www.srghousing.com	एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	
पहिलिएट – 4 (नियम 8 (1)) डाकैतिक की सूचना (ह्यावर समिति के लिए)		
अयोहस्ताक्षरी, को एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी है, ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए एवं संश्लिष्ट प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत निम्न ऋणी/सहऋणी/जमानतियों /बन्धककर्ताओं को एक मांगपत्र जिसमें उल्लेखित रकम, जो उक्त सूचना पत्र की प्राप्ति की तारीख से 60 दिवस के भीतर प्रिदिवाय करने के लिए " मांग पत्र " जारी किया था । ऋणी/सहऋणी/जमानतियों /बन्धककर्ता द्वारा रकम का प्रिदिवाय करने में असफल रहने पर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता, उनके जमानतदारों एवं जमानतधारों का यहाँ सूचना दी जाती है की अयोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं संश्लिष्ट प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002, के नियम 8 के अंतर्गत निम्न संश्लिष्ट का सांकेतिक कब्जा उल्लेखित दिनांक को से लिया है । ऋणी/सहऋणी, बन्धककर्ता व जमानतदारों को विशिष्ट रूप से एवं जनाधारण को सामान्य रूप से इसके द्वारा सावधान किया जाता है की वह नीचे वर्णित संघितियों के सम्बन्ध में कोई व्यवहार नहीं करे । इन संघितियों के संबंध में किया गया कोई भी व्यवहार नीचे डाकैतिक कब्जा पत्र में वर्णित रकम, और सांकेतिक कब्जा पत्र की दिनांक से आगे के ब्याज, छत्रां, अन्य छत्रां आदि के लिए एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 321, एस.एम. लोहा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री लॉकल के पास, उदयपुर – 313001 (राजस्थान) के प्रभार के अधीन होगा । अयोहस्ताक्षरी उक्त अधिनियम की धारा 13 की अध्वारा (8) के अंतर्गत सुरक्षित (सिक्वेर्ड) प्रतिभूति के उन्मोचन के लिए उपलब्ध समय के प्रावधानों की ओर ऋणी, सहऋणी, बन्धककर्ता व उनके जमानतदारों का ध्यान आकृष्ट करता है ।		
क्र. ऋण खाता संख्या/ ऋणी/ सहऋणी/ जमानती सं.	1) मांग पत्र की दिनांक 2) मांग पत्र की दिनांक 3) मांग पत्र मांग पत्र अनुसार	स्थावर संघित की विवरण
1. HLR0000000000015813 श्री खुशाल लाल माली पुत्र श्री गुलाब माली (ऋणी) श्रीमती बाबुडी माली पत्नी श्री खुसाजी माली (सह-ऋणी-1)	अक्टूबर 13, 2025 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- फरवरी 09, 2026	श्री खुसा लाल माली पुत्र श्री गुलाब माली जी की सम्पति को की मिसल सं.- 9/2004, संकल्प सं.- 8 (20-9-2006), सम्पति सं.-05, ग्राम-भील भागरा, ग्राम पंचायत-धोसुण्डी, तहसील-आमेट, जिला-राजसमन्द- (राजस्थान) पर स्थित है जिसमें भूमि, भवन एवं सुरेश पुत्र श्री गुलबज (सह-ऋणी-3) श्री गुरा लाल पुत्र श्री मोहन लाल (जमानती-1) श्री अमृत लाल माली पुत्र श्री भंवर लाल माली (जमानती-2)
	1) मांग पत्र की दिनांक- अक्टूबर 13, 2025 2) सांकेतिक कब्जे की दिनांक- फरवरी 09, 2026 3) मांग पत्र मांग पत्र अनुसार- ₹ 10,28,380 /- रुपये दस लाख अठाईस हजार तीन सौ अस्सी मात्र जिसका माप लगभग 1116.50 वर्ग फीट है । जिसकी दिनांक अक्टूबर 07, 2025 तक ब्याज वृत्तसीमा निम्न है- पूर्व-रास्ता और एकलिंग माली का अक्टूबर 08, 2025 से आगे के ब्याज, छत्रां अतिरिक्त ।	श्री मकान, पश्चिम- रास्ता और सुरेश माली का मकान, उत्तर-आम रास्ता, दक्षिण-रास्ता और हीरा राम हीर लाल माली का मकान
स्थान- राजस्थान प्रकाशन की दिनांक- 13/02/2026		अधिकृत अधिकारी एसआरजी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, "अ" श्रेणी निम्बाहेड़ा	
दूरभाष – कार्यालय फोन-01477 –220040 ईमेल- kums.nimbahae@rajasthan.gov.in	

कृषि उपज मण्डी समिति, निम्बाहेड़ा के फल-सब्जी मण्डी प्रांगण में चिह्नित एवं रिक्त दुकान /गोदाम भूखण्डों के आवंटन हेतु इस कार्यालय से जारी विज्ञापित क्रमांक 1250-1266 दिनांक 12.03.2022 एवं क्रमांक 333-348 दिनांक 27.06.2022 के क्रम में अनुज्ञापत्रकारी संयुक्त/ 'क' वर्ग दलाल /व्यापारी वर्ग निशक्तजन अनुज्ञापत्रकारी व्यापारी वर्ग एवं महिला कुक्क (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं किसान) वर्ग तथा जैविक खेती उत्पाद कुक्क वर्ग, अनुज्ञापत्रकारी तेल मील एवं अन्य कृषि निम्न प्रसंकरण इकाई वर्ग, पंजीकृत कुक्क उत्पादक संगठन /कम्पनी एवं वन उपज /औषधी पादप /जडी बूटी के अनुज्ञापत्रकारी व्यापारी वर्ग के अंतिम दिनांक तक प्राप्त आवेदन पत्रों के दिये अपेक्षित एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर जांच एवं सत्यापन किए जाने के उपरान्त अगल सम्पत्ति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(4) की पालना में निम्नानुसार पात्र एवं अपात्र सूची जारी की जाती है । अगल संपत्ति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1)के तहत 01.04.2010 के पूर्व अनुज्ञापत्रकारी जो कि निरन्तर व्यवसायरता हो उन्हें निम्नितर आरक्षित दर पर सर्वप्रथम आवंटन किया जाएगा ।			
भूखण्ड साईज 15'9" X 27'6" +20 (15 दुकान /गोदाम मय प्लेटफॉर्म)			
अगल सम्पत्ति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1) के तहत पात्र आवेदकों की सूची			
क्र. सं.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र क्रमांक व दिनांक	विधि.
1	2	3	4
1	मैसर्स मुन्ना खाँ मोहम्मद खाँ	01/28.04.1995	पात्र
2	मैसर्स दुर्गाशंकर गणेशलाल माली	10/30.10.1999	पात्र
अगल सम्पत्ति आवंटन नीति 2005 के बिन्दु संख्या 7(1)(1) के तहत अपात्र आवेदकों की सूची			
क्र. सं.	फर्म का नाम	अनुज्ञापत्र क्रमांक व दिनांक	अपात्रता का कारण
1	2	3	4
1	मैसर्स कन्हैयालाल नाथगणलाल माली	94 / 31.03.1999	मुख्य मण्डी प्रांगण में पूर्व में दुकान / गोदाम भूखण्ड आवंटित है
2	मैसर्स अर्जुनलाल मोहनलाल माली	92/ 31.03.1999	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
3	मैसर्स राजू एण्ड इन्द्रस	306 / 17.06.2003	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
3	मैसर्स ईश्वर फुट कम्पनी	424 / 17.06.2009	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
4	मैसर्स महादेव सक्की भण्डार	375 / 04.07.2008	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
5	मैसर्स शिव ड्रेडर्स	496 / 10.02.2012	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
6	मैसर्स उदालासाई मुन्ना भाई	495 / 10.02.2012	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
7	मैसर्स बरामाजी बेजीदेखल कम्पनी	603 / 29.06.2015	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
8	मैसर्स तरुण कुमार नौनदलाल	494 / 10.02.2012	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
9	मैसर्स जयनारायण फुट कम्पनी	618 / 03.09.2015	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
10	मैसर्स हेमन्त कुमार किशनलाल माली	616 / 03.09.2015	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
11	मैसर्स शंकर फुट कम्पनी	556 / 04.03.2014	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
12	मैसर्स कालुलाल मोहनलाल माली	719 / 10.08.2017	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
13	मैसर्स देवीलाल मोहनलाल माली	498 / 10.02.2012	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
14	मैसर्स बाबूलाल मोहनलाल माली	716 / 10.05.2017	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
15	मैसर्स उदाललाल मोहनलाल माली	718 / 28.08.2017	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
16	मैसर्स नरेश सक्की भण्डार	722 / 24.08.2017	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
17	मैसर्स मिवार फुट कम्पनी	615 / 03.09.2015	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
18	मैसर्स शिव आनन्द सक्की भण्डार	607 / 05.08.2015	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
19	मैसर्स आशिक हुसैन एण्ड सन्स	803 / 14.06.2021	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
20	मैसर्स ऐन. जी. कम्पनी	826 / 23.11.2021	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण
21	मैसर्स जे.के.के. सलायर्स	730 / 30.12.2017	विधित्व वर्ष 2010-11 से लगातार व्यवसाय नहीं करने के कारण

प्रदेश में मा. शि. बोर्ड की परीक्षायें शुरु

पहले दिन सैकेण्डरी की अंग्रेजी अनिवार्य तथा सीनियर सैकेण्डरी की मनोविज्ञान की परीक्षा हुई

अजमेर, (कासं)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आयोजित बोर्ड परीक्षाओं की गुब्बारा से औपचारिक शुरुआत हो गई। पहले दिन सैकेण्डरी में अंग्रेजी अनिवार्य तथा सीनियर सैकेण्डरी में मनोविज्ञान विषय की परीक्षा आयोजित की गई। कक्षा 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा देकर बाहर आए विद्यार्थियों की प्रतिक्रियाएं मिली-जुली रही, कई छात्रों ने प्रश्नपत्र को सरल बताया, जबकि कुछ ने इसे थोड़ा कठिन करार दिया। परीक्षा केंद्रों के बाहर विद्यार्थियों में हल्की घबराहट के साथ-साथ संतोष भी देखने को मिला। अधिकांश छात्राओं का कहना था कि प्रश्नपत्र पाठ्यक्रम के अनुसार था और समय पर पूरा हो गया। वहीं कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि प्राम् और रीडिंग सेक्शन के कुछ प्रश्न अपेक्षाकृत कठिन थे, जिनमें सोचने में अधिक समय लगा।

इधर, बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ स्वयं सक्रिय नजर आए। उन्होंने बोर्ड परिसर में संचालित कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और विभिन्न परीक्षा केंद्रों की व्यवस्थाओं की



प्रदेश के कई परीक्षा केंद्रों पर गुरुवार को 10वीं व 12वीं की परीक्षा हुई।

समीक्षा की। बोर्ड सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि परीक्षाएं पूरी पारदर्शिता और अनुशासन के साथ संपन्न कराई जाएं, ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या नकल की शिकायत न आए। बोर्ड सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ के अनुसार इस वर्ष बोर्ड परीक्षाओं के लिए 19 लाख 90 हजार 57 परीक्षार्थी

पंजीकृत हैं। प्रदेशभर में 6194 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। सुरक्षा और गिरगनी के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं तथा सवेदनशील केंद्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर बोर्ड परीक्षाओं का पहला दिन सफल और शांतिपूर्ण रहा। अब आने वाले दिनों में अन्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित

होंगी, जिनको लेकर विद्यार्थी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं नकल रहित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से गिरगनी की जा रही है। उड़नदस्तों और विशेष दलों की तैनाती की गई है। इस बार अभय कर्मांड सेंटरों के माध्यम से भी जिलों

- 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा देकर बाहर आए कई छात्रों ने प्रश्नपत्र को सरल बताया, जबकि कुछ ने इसे थोड़ा कठिन करार दिया
- बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्थाओं को लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ सक्रिय नजर आए

के परीक्षा केंद्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है। बोर्ड परिसर में परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व बोर्ड प्रशासक एवं संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ तथा सचिव गजेन्द्र सिंह राठौड़ सहित अधिकारियों ने विधिवत पूजा-अर्चना की और सीसीटीवी कक्ष व कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया।

उदयपुर : सिलाई कर रही महिला पर चाकू से हमला , हालत गंभीर

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर जिले के कुराबड थाना क्षेत्र में बुधवार देर शाम सिलाई का काम कर रही एक महिला पर अज्ञात बदमाश ने चाकू से हमला कर दिया। महिला गंभीर घायल हो गई, जिसके बाद उसे एमबी हॉस्पिटल रेफर किया गया। खून ज्यादा बहने से महिला की हालत गंभीर बनी हुई है।

हॉस्पिटल में भर्ती घायल महिला ने बताया कि हमले के दौरान वह चिल्लाती हुई दुकान से बाहर आई और लोगों से मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन लोग तमाशे की तरह देखते रहे। किसी ने मेरी मदद नहीं की। थानाधिकारी तेजु सिंह ने बताया कि कुराबड के ब्रह्मपुर में आसपास (35) पुत्री फैजाना शाह अपनी दुकान पर सिलाई कर रही थी। तभी अज्ञात व्यक्ति ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। महिला घायल हो गई, जिसका इलाज जारी है। पुलिस आसपास सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपी की तलाश में जुटी है।

जाकारारी अनुसार आरोपी अपने बहन के कपड़े सिलाई के बाद लेने की बात कह रहा था, लेकिन पीड़िता ने ऐसे कोई कपड़े होने से इंकार कर दिया। इसके बाद आरोपी वहां से चला गया।

- बदमाश ने महिला की गर्दन, सिर और हाथ पर तीन वार किए
- पुलिस आसपास सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपी की तलाश में जुटी

फिर करीब 20 मिनट बाद वापस लौटा और सिलाई करती महिला पर चाकू से हमला कर दिया। बदमाश ने महिला की गर्दन, सिर और हाथ पर तीन वार किए। जिससे वह घायल हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गया। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना पर कुराबड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। पुलिस घटना के स्पष्ट कारणों की तलाश में जुटी है। घायल महिला की मामी गुलनाज बानो के अनुसार आरोपी ने यासमीन पर तीन बार चाकू से वार किए। मौके पर लोग जमा हो गए थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हम घायल को हॉस्पिटल लाए तब भी पुलिस साथ नहीं थी।

महिला की चेन छीनने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के सविना थाना पुलिस ने महिला दुकानदार को चाकू दिखा उसके गले से सोने की चेन छीनने के मामले में पहाड़ा थाने के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया।

प्रकरण के अनुसार 11 फरवरी को पीड़िता सुनिता पत्नी बड़ीलाल कलाल निवासी तीतरड़ी अम्बामाता घाटी सविना ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया कि मेरी गायत्री किरणा स्टोर पर शाम को मुंह बांध कर दो लड़के आए तथा सिगरेट लेने के बहाने बातचीत करते हुए मेरी गर्दन पर झपट्टा मार कर सोने की चेन छीन कर भाग रहे थे। इसको देख चिल्लाने पर लोगों ने घेरा डाल कर पकड़ लिया, लेकिन एक बदमाश चाकू दिखा कर बाइक से उतर कर फरार हो गया। डिटेन्शुदा बाल अपचारी की सूचना मिलने पर सविना थानाधिकारी गजवीरसिंह मय टीम ने जोगी तालाब 200 फीट रोड़ के समीप झाड़ियों में छिपा भवर लाल पुत्र लक्ष्मण लाल मीणा निवासी सैरफा फला बिचला पहाड़ा पुलिस को जांच की कर भागा जो गिरने पर चोटिल होने पर चिकित्सालय में उपचार कराया। भवरलाल पहाड़ा थाने का बदमाश होकर उसके खिलाफ कई अपराधीक प्रकरण दर्ज होने के बाद एसएसआई लोकेश कुमार कर रहे हैं।

महिला की चेन छीनने वाला गिरफ्तार

उदयपुर, (कासं)। शहर के सविना थाना पुलिस ने महिला दुकानदार को चाकू दिखा उसके गले से सोने की चेन छीनने के मामले में पहाड़ा थाने के शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। प्रकरण के अनुसार 11 फरवरी को पीड़िता सुनिता पत्नी बड़ीलाल कलाल निवासी तीतरड़ी अम्बामाता घाटी सविना ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करवाया कि मेरी गायत्री किरणा स्टोर पर शाम को मुंह बांध कर दो लड़के आए तथा सिगरेट लेने के बहाने बातचीत करते हुए मेरी गर्दन पर झपट्टा मार कर सोने की चेन छीन कर भाग रहे थे। इसको देख चिल्लाने पर लोगों ने घेरा डाल कर पकड़ लिया, लेकिन एक बदमाश चाकू दिखा कर बाइक से उतर कर फरार हो गया। डिटेन्शुदा बाल अपचारी की सूचना मिलने पर सविना थानाधिकारी गजवीरसिंह मय टीम ने जोगी तालाब 200 फीट रोड़ के समीप झाड़ियों में छिपा भवर लाल पुत्र लक्ष्मण लाल मीणा निवासी सैरफा फला बिचला पहाड़ा पुलिस को जांच की कर भागा जो गिरने पर चोटिल होने पर चिकित्सालय में उपचार कराया। भवरलाल पहाड़ा थाने का बदमाश होकर उसके खिलाफ कई अपराधीक प्रकरण दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था।

बोरवेल खुदाई में निकली चांदी जैसी धातु लूटने पहुंचे लोग

अलवर, (निसं)। अलवर में बोरवेल करते समय चांदी जैसी धातु के टुकड़े निकले। यह सब देखकर सबसे पहले बोरवेल करने वाले मजदूर ही पत्थर लूटने लगे। इसके बाद आसपास के दुकानदार और लोग भी धातु के टुकड़े ले गए। मामला अल्कापुरी इलाके में गुरुवार को करीब 1:30 बजे का है। यह बोरवेल जलदाय विभाग की ओर से करवाया जा रहा है। फिलहाल काम को रोक दिया है।

बोरवेल कर रहे मजदूर शाहरुख खान ने बताया कि यहां से लोग करीब 10 से 15 किलो वजन के चांदीनुमा पत्थर ले गए। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि जमीन के नीचे से आए चमकीले पत्थरों में चांदी कितनी प्रतिशत है। बोरवेल करते समय करीब 800 फीट तक मशीन से खुदाई हुई तो पानी-मिट्टी के प्रेशर के साथ नीचे जमीन से चांदी जैसी धातु के पत्थर निकले।

मजदूर शाहरुख खान ने बताया कि यहां 800 फीट गहरा बोरवेल करना था। इसमें आखिरी में जमीन की 20 फीट खुदाई तक मशीन पहुंची, तब यह चमकीला पत्थर निकलने लगा। आम तौर पर बोरवेल के नीचे से अलग-अलग तरह के पत्थर आ जाते हैं, लेकिन यह कुछ अलग है। इसमें धातु हो सकती है। आखिरी में करीब 5 से 10 प्रतिशत ऐसा पत्थर आया है। मशीन पर काम

सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला

बीकानेर, (निसं)। जिले के सीमावर्ती क्षेत्र छतरगढ़ में एक बार फिर पाकिस्तानी गुब्बारा दिखाई दिया है। पहले भी कई बार ऐसे ही गुब्बारे सीमावर्ती क्षेत्र में मिले हैं, जिन पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाईंस लिखा हुआ है। गुब्बारा मिलने की सूचना मिलते ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना कर दी।

छतरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और गुब्बारे को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने गुब्बारे की स्थिति, उस पर लिखे शब्दों और उसके आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है जब छतरगढ़ या बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में इस तरह के गुब्बारे मिले हों। इससे पहले भी कई बार बॉर्डर इलाके में पाकिस्तान की ओर से भेजे गए गुब्बारे बरामद हो चुके हैं। कई बार इन गुब्बारों पर अलग-अलग कंपनियों, संस्थानों या पाकिस्तान से जुड़े नाम भी लिखे मिले हैं। सीमा पार से ऐसे गुब्बारे अक्सर सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान भटकाने, क्षेत्र में भ्रम फैलाने या किसी संदिग्ध गतिविधि को अंजाम देने की मंशा से भेजे जाते हैं। ऐसे मामलों में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाती हैं क्योंकि कई बार इन गुब्बारों के साथ संदिग्ध सामग्री, संदेश या तकनीकी उपकरण भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस का कहना है कि फिलहाल गुब्बारे की जांच की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर इसे सुरक्षा एजेंसियों व विशेषज्ञ टीम को सौंपा जाएगा।

Office of the Medical Superintendent
RUHS Hospital, Jaipur
Sector-11, Kumbha Marg, Pratap Nagar, Jaipur-302033
Ph. 0141-2792253 Email: supdt.hms@ruhsraj.org
Date: 09/02/2026

No. RUHS/HMS/Manpower/2025-26/13922

अल्पकालीन ई निविदा सूचना

राज.स्वा.वि.वि.आयुर्विज्ञान चिकित्सालय में कार्य की प्रकृति के आधार पर अकृशल, कुशल एवं उच्च कुशल मैन पावर सेवाओं के उद्योगन हेतु निर्धारित दर सविदा प्रपत्र अनुसार ई उद्योगन प्रक्रिया के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। (कुल अनुमानित लागत राशि रु. 600 लाख)

1.	Bid Download Start Date/Time	09/02/2026 from 05:00 PM onwards
2.	Bid Submission Start Date/Time	09/02/2026 from 05:00 PM onwards
3.	Bid Submission End Date/Time	06/03/2026 at 02:00 PM
4.	Technical Bid Opening Date/Time	07/03/2026 at 02:00 PM

* Details may be seen in the bidding document at <https://eproc.rajjasthan.gov.in> or <https://sppp.rajjasthan.gov.in>

UBN: CMS2526SLRC00115

Raj.Samwadi/C/25/19737

Medical Superintendent
RUHS Hospital, Jaipur

राजस्थान-सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान

आबकारी भवन-2 गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर-313001

क्रमांक-F.32(B)(After Policy 2026-27)/ex/1/2026-06481-9018219/693

दिनांक-11.02.2026

कम्पोजिट रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2025-26 के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2026-27 के लिये अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिये आवेदन (विकल्प प्रस्तुत करने की नियत तिथि को बढ़ाई जाने की सूचना)

इस कार्यालय की समसंख्यक विज्ञापित क्रमांक 665 दिनांक 28.01.2026 के सन्दर्भ में राज्य के कम्पोजिट रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2025-26 के समस्त अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के समस्त अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2026-27 के लिए अनुज्ञापत्रों के नवीनीकरण के लिए पात्र एवं इच्छुक अनुज्ञाधारी अपना नवीनीकरण आवेदन (विकल्प) पत्र मय निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ दिनांक 16.02.2026 तक संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। दिनांक 16.02.2026 तक नवीनीकरण आवेदन (विकल्प) प्राप्त नहीं होने पर अनुज्ञाधारी का नवीनीकरण कवाने का विकल्प समाप्त हो जावेगा। तथा दुकान/समूह (Cluster) का आवेदन ई-नीलामी/ई-निविदा द्वारा किया जाएगा। वर्ष 2026-27 हेतु अनुज्ञापत्र नवीनीकरण से संबंधित समस्त जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajjasthan.gov.in> का अवलोकन करें। अन्य सभी भर्त पूर्तानुसार यथावत रहेंगे।

आबकारी आयुक्त, राजस्थान

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
PHED DIVISION KARauli**

PHNO.-07464-250219 E-Mail-ee.kar.phed@rajasthan.gov.in

Notice Inviting Bid

Bids for various works under summer contingency are invited from interested bidders up to 24.02.2026 other particulars of the bid may be visited eproc.rajjasthan.gov.in and sppp.raj.nic.in website. on the procurement portal

NIB CODE:-PHE2526SA5986

S.N.	NIT NO.	UBN	S.N.	NIT NO.	UBN
1	142/2025-26	PHE2526WSOB12758	9	150/2025-26	PHE2526WSOB12771
2	143/2025-26	PHE2526WSOB12759	10	151/2025-26	PHE2526WSOB12773
3	144/2025-26	PHE2526WSOB12762	11	152/2025-26	PHE2526WSOB12774
4	145/2025-26	PHE2526WSOB12763	12	153/2025-26	PHE2526WSOB12776
5	146/2025-26	PHE2526WSOB12765	13	154/2025-26	PHE2526WSOB12777
6	147/2025-26	PHE2526WSOB12766	14	155/2025-26	PHE2526WSOB12779
7	148/2025-26	PHE2526WSOB12769	15	156/2025-26	PHE2526WSOB12780
8	149/2025-26	PHE2526WSOB12770	16	157/2025-26	PHE2526WSOB12781
01		Total work			16
02		Total Estimate Cost			63.29 Lac
03		Bid submission end date			24.02.2026 up to 06.00 PM
04		Bid opening date			25.02.2026 at 02.00 PM

(Vijay Kumar Meena)
Executive Engineer
PHED Division Karauli

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता (एम.एम.-प्रथम)
पुराना पॉवर हाउस, बनीपार्क, जयपुर टेलीफ़ैक्स: 0141-2208098

निविदा सूचना

एल टी एक्स एल पी ई इंसुलेटेड एरियल ब्रन्ड केबल, बेयर मेसेन्जर वायर के साथ (1Cx25+25 Sq.mm) केबल संख्या- 5071) (UBN- VVN2526GLOB00979), 2 कोर एलटी पीसीसी आरएमएस केबल (2Cx4 Sq.mm) (निविदा संख्या-5072) (UBN- VVN2526GLOB00980), ए सी एस आर डोंग कंवक्टर (निविदा संख्या-5073) (UBN- VVN2526GLOB00981), फ़ैबीकेट स्टील आइटम (ब्लेड्स) 33 केबी कॉस आर्म्स मय क्लैम्प (एंगल) व टॉप हैम्पर, 11 केबी कॉस आर्म्स (65X65X6) मय क्लैम्प (एंगल) व टॉप हैम्पर, 11 केबी टॉप हैम्पर बिना क्लैम्प, एलटी कॉस ब्रेकेट 4" लम्बे एवं 2" लम्बे, (निविदा संख्या-5074) (UBN- VVN2526GLOB00983), 33 केबी जी आई पिन (निविदा संख्या-5075) (UBN- VVN2526GLOB00982), 11 केबी पिन इन्सुलेटर (पॉलीमर) (निविदा संख्या-5076) (UBN- VVN2526GLOB00984), 11 केबी पिन इन्सुलेटर (पॉलीमर) (निविदा संख्या-5077) (UBN- VVN2526GLOB00985), 45 के एन टी एण्ड सी टाइप टाइप ड्रिक इन्सुलेटर (पॉलीमर) (निविदा संख्या-5078) (UBN- VVN2526GLOB00986), 11 केबी हॉर्न गैप फ्यूज सेट पोस्ट इन्सुलेटर के साथ (निविदा संख्या-5079) (UBN- VVN2526GLOB00987), 33 केबी एवं 11 केबी आईसीलेटर के फिक्स्ड कॉन्टेक्ट (जॉ) एवं मुविंग कॉन्टेक्ट (पाइप) (निविदा संख्या-5080) (UBN- VVN2526GLOB00988) की खरीद हेतु ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के अन्तर्गत निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा के बारे में अन्य विवरण वेबसाइट www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं <http://energy.rajjasthan.gov.in/jvnl> द्वारा जाने जा सकते हैं। भविष्य में निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन / तिथि बदले की जानकारी केवल वेबसाइट www.eproc.rajjasthan.gov.in एवं <http://energy.rajjasthan.gov.in/jvnl> पर उपलब्ध कराई जाएगी। जेबीकार-3121 (2026) एच.सं.वार /सी / 25 / 19727

अधीक्षण अभियन्ता (एम. एम. प्रथम)
बिजली विभागों के लिए टेंडर की नम्बर 1800 180 6507

कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

टाउन-नॉर्थ लिंक रोड, उदयपुर (राज.) 313001

दुरभाष सं 0294-2421255, 2420013, Helpline no. 0294-2426262 वेबसाइट- www.mcdudipur.org

क्रमांक:- एच.सी. / 2025.26 / 209 दिनांक:-10.02.26

ई-बोली आमन्त्रण सूचना संख्या-ई- 01/2025-26

नगर निगम उदयपुर द्वारा अल्पाहार, भोजन व पानी कैंपेर सलाई कार्य की दर सविदा हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा की अनुमानित लागत 30.00 लाख है। ऑनलाइन निविदा पार्श्व मिलने की प्रारंभ दिनांक 11.02.26 अंतिम दिनांक 23.02.26 तथा खुलने की दिनांक 24.02.26 रहेंगी।

UBN No. UNP2526GLRC00150 आयुक्त नगर निगम, उदयपुर

राज.सं.वार /सी / 25 / 19723

कार्यालय नगर पालिका हिण्डोली जिला - बून्दी (राज0)

क्रमांक :- न0पाशि0/निर्माण / 2025-26 / 3265 दिनांक :- 09.02.2026

ई-निविदा सूचना संख्या 22 /2025-26

नगर पालिका हिण्डोली द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु नगर पालिका हिण्डोली में पंजीकृत कार्यों के अनुसार स्वाम स्वतः के संवेद्यक एवं अन्य विभागों में पंजीकृत A.A.A. श्रेणी के संवेद्यकों से डी लिक्वाका पद्धति/ई-निविदा पद्धति से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। कार्य की निविदा बेचे जाने की दिनांक 10.02.2026 से तथा अपलोड करने की दिनांक 10.02.2026 से दिनांक 23.02.2026 तक है। जिसकी कुल लागत 54.50 लाख है। निविदा भरें आदि सम्पूर्ण विवरण <http://sppp.raj.nic.in>, <http://eproc.rajjasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है। NIB CODE:-DLB2526B1447

Sr.No.	UBN No.	Tender Cost in lakh
1	DLB2526WSRC33761	24.96
2	DLB2526WSRC33762	29.54

राज.सं.वार /सी / 25 / 19697 प्रशासक अधिशाही अधिकारी

कार्यालय नगर परिषद टोंक

क्रमांक :-न.प.टी.क./निर्माण / 2025-26 / 14290 दिनांक :- 09.02.2026

NOTICE INVITING TENDERS THROUGH NIT No 87 / 2025-26

Bids are invited from interested bidders from 10.02.2026 (10.00AM) to 23.02.2026 (6.00PM) as per following details. Other particulars of he bid may be visited on procurement portal (www.Sppp.Rajasthan.gov.in) of the state NIB No. DLB2526B1403

NIT No.	Name of work	UBN No.
87/2025-26	आईडीएआरएमटी कॉलोनी मे सेक्टर नं. बी एवं सी के पार्क का सौन्दर्यकरण करने का कार्य (अनुमानित राशि 29.98 लाख)	DLB2526WSOB33593

Date & time of opening of tender 24.02.2026 at 3.00PM

अति0 जिला कलक्टर आयुक्त एवं प्राधिकारी / प्रशासक नगर परिषद, टोंक

राज.सं.वार /सी / 25 / 19677 न0पटी0क

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, कोटा

राजभवन रोड, सिविल लार्न्स, नयापुर, कोटा-324001 दूरभाष/फैक्स 0744-2322747 (ई मेल आई.डी. dcfl.kota.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक- एफ।1 स्टीर/असई/2025-26/890 दिनांक-01.02.2026

ई-निविदा सूचना संख्या 48/2025-26

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से MSME / SSI Unit / अधिकृत पंजीकृत निर्माताओं/ विक्रेताओं/सप्लायर्स से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आरएफबीडीपी योजना-न्तर्गत इस कार्यालय के अधीन विभिन्न रेंजों लाडपुरा, मण्डाना, मोक्ष, कनवास, सुल्तापुर, ईटावा एवं खालोती के क्षेत्राधिकारी अधीन राजकीय विद्यालयों हेतु विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था हेतु आयर्न टेबल कम बेंचस को क्रय करने के लिए द्वि-स्तरीय निविदा प्रक्रिया के माध्यम से वार्षिक दर अनुबंध पद्धती के आधार पर ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।

उक्त निविदा को ऑनलाईन भरने की अंतिम तिथि 15.02.2026 को सायं 06.00 बजे तक है। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण निम्नानुसार साईट्स परदेखा जा सकता है। <https://sppp.rajjasthan.gov.in> एवं www.eproc.rajjasthan.gov.in

UBN NO. 1- FOR2526WSOB05315 (अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव) उप वन संरक्षक कोटा (राज.)

DIPRC/2711/2026

भारत-पाक बॉर्डर पर 10 करोड़ की हेरोइन मिली

बीकानेर, (निसं)। भारत-पाक बॉर्डर पर बीकानेर जिले के खाजुवाला क्षेत्र में एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हेरोइन गिराई गई है। बॉर्डर से 2 किमी दूर मिला 2 किलो 25 ग्राम हेरोइन जिसे खाजुवाला के कार्यवाहक एसएसआई हरपाल सिंह ने बताया कि मंगलवार देर रात बॉर्डर के पास संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली थी। आशंका थी कि ड्रोन के जरिए मादक पदार्थ गिराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। रात करीब एक बजे तक 14 बीटी के पास बॉर्डर से करीब दो किलोमीटर दूर एक पीले रंग का पैकेट बरामद हुआ। जांच में उसमें करीब 2 किलो 25 ग्राम हेरोइन होने की पुष्टि हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बरामद पैकेट में दो

- बीकानेर जिले के खाजुवाला क्षेत्र में ड्रोन से गिराई गई थी हेरोइन

छड़ें लगी हुई थी, जिन्हें संभवतः ड्रोन से जोड़कर गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया। शुरुआती जांच में साफ है कि तस्करों ने ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर सीमा पार से खप भेजी। पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ थाना प्रभारी समरवीर को सौंपी है। आसपास के क्षेत्र में सर्वे ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खाजुवाला क्षेत्र में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 8 जनवरी को चक 40 के जेडी में भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराई गई करीब छह करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद की गई थी। उस समय 500 ग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी।

बेटी की शादी के एक दिन पहले मां की हादसे में मौत

देवर के साथ कार्ड बांटकर लौटते समय बाइक से गिर गई थी महिला

डूंगरपुर, (निसं)। सदर थाना क्षेत्र में पालवड़ा के पास देवर की बाइक के पीछे बैठी भाभी की नीचे गिरने से मौत हो गई। बेटी की शादी के एक दिन पहले ही मां की मौत से परिवार ने मातम पससर गया। देवर और भाभी दोनों ही शादी के कार्ड बांटने के बाद वापस घर लौट रहे थे।

सदर थाना पुलिस के अनुसार धर्मनारायण मीणा निवासी कलावत फला आमली डूंगरी थाना ऋषभदेव

उदयपुर की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इसमें बताया कि उसकी बेटी की 13 फरवरी को शादी है। बुधवार को पत्नी काली देवी (50) और छोटा भाई कांतिलाल दोनों ही बाइक लेकर शादी के कार्ड बांटने डूंगरपुर के देवल गांव गए थे। दोनों ही निर्मंत्रण पत्र देकर वापस बाइक से जा रहे थे। पालवड़ा स्कूल के पहले ही महिला काली देवी अचानक बाइक से नीचे गिर गईं। महिला के हाथ, पैर और सिर पर गंभीर

चोटें आईं। उसे तुरंत डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए, जहां इमरजेंसी में डॉक्टर ने जांच के बाद काली देवी की मृत घोषित कर दिया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। हादसे के बाद शादी के घर में मातम पसर गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है।

राजस्थान आवासन मण्डल
हमारा प्रयास, सबको आवास

ई-ऑक्शन के माध्यम से

व्यावसायिक / आवासीय प्रीमियम संपत्तियों को खरीदने का सुनहरा अवसर

ई-ऑक्शन 25 से 27 फरवरी, 2026

बड़े व्यावसायिक भूखण्ड	स्वतंत्र निर्मित आवास एवं फ्लैट
जयपुर - 10	अलवर - 01
भिवारी - 18	भरतपुर - 01

आवासीय भूखण्ड

जयपुर - 04 अलवर - 06 || जोधपुर - 02 | |

RERA Website: www.rera.rajjasthan.gov.in

ईएमडी राशि न्यूनतम बोली मूल्य की 2% होगी एवं बोली/ई-नीलामी आरम्भ होने से 5 दिन पूर्व जमा कराई जा सकेगी एवं 24 घंटे पूर्व तक स्वीकार की जा सकेगी।

वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी एवं अन्य शर्तों के लिए QR कोड स्कैन करें
*भवन निर्माण पैरामीटर्स भवन विनियम 2025 के अनुसार रहेंगे।

हेल्पलाइन नं. कार्यालय समय में: 0141-2744688, 2740009, कार्यालय समय उपरान्त: 9461054291/92/319 एवं 6376868696, 9460254319

आवेदन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रार के माध्यम से

आवासन आगुक्त

राज.सं.वार /सी / 26 / 19749

राज्य बजट 2026-27 में किसान कल्याण पर विशेष फोकस

राजस्थान में कृषि क्षेत्र के लिए 1.19 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में किसान कल्याण पर विशेष फोकस रखा है। बजट वर्ष 2026-27 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए रिकॉर्ड एक लाख 19 हजार 408 करोड़ 11 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। यह राशि गत वर्ष की तुलना में 7.59 प्रतिशत अधिक है। सरकार का दावा है कि इन प्रावधानों से किसानों की आय, उत्पादकता और कृषि अवसरंचना को नई मजबूती मिलेगी तथा राजस्थान को देश का अग्रणी कृषि राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

590 करोड़ रुपये का ऋण 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे करीब 26 हजार किसान एवं लघु उद्यमी लाभान्वित होंगे।सिंचाई और खेतों की आधारभूत सुविधाओं के लिए 585 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान प्रस्तावित है। इसके तहत 8 हजार डिगियाँ, 15 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन तथा अगले दो वर्षों में 36 हजार फार्म पॉण्ड बनाए जाएंगे, जिससे 80 हजार से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

■ रबी दलहनों का उत्पादन 22.34 प्रतिशत वृद्धि के साथ 26.61 लाख मैट्रिक टन अनुमानित

■ मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना में लक्ष्य के मुकाबले 99 प्रतिशत से अधिक गुणवत्तापूर्ण बीज वितरित

50 हजार किसानों को 20 हजार किलोमीटर तारबंदी के लिए 228 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। सामुदायिक तारबंदी में न्यूनतम कृषक संख्या 10 से घटकर 7 कर दी गई है। इसके अलावा 50 हजार किसानों को कृषि यंत्रों पर 160 करोड़ रुपये का अनुदान तथा 500 कस्टम हार्वरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे।

राज्य में उन्नत बीजों को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख किसानों को मूंग, 1-1 लाख किसानों को मोठ और ज्वार-बाजरा-बरसीम के मिनीकित वितरित किए जाएंगे। 2.50 लाख किसानों को दलहनी और तिलहनी फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। पांच हजार से अधिक आबादी वाली 3496 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से वर्मी कम्पोस्ट इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। प्रथम चरण में 2098 ग्राम पंचायतों में लगभग 270 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

किसानों को जलवायु जोखिम से बचाने के लिए डिजिटल कृषि मिशन के तहत 'राज कृषि सूचना एवं प्रबंध प्रणाली' विकसित की जाएगी। एआई, एमएल, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से मौसम आधारित बुवाई, फसल स्वास्थ्य निगरानी और जोखिम प्रबंधन की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

प्रदेश के विशिष्ट कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 'मिशन राज गिफ्ट' भी

प्रारंभ किया जाएगा।

राजस्थान कॉर्पोरेट डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट फंड को 1000 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये किया गया है। 'सरस' ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए एनसीआर, यूपी और एमपी में आउटलेट्स खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत 5 लाख पशुपालकों को लाभान्वित करने के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत 1.12 लाख किंवदंतल बीज वितरित किए गए। नई किस्मों के 31.50 लाख बीज मिनीकित निःशुल्क दिए गए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 6,206 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में 10.63 लाख पशु और 5.54 लाख परिवार लाभान्वित हुए। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को 1,070 कृषि ड्रोन खरीदने पर 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया गया।

विधायक रोहित बोहरा ने किया

अभद्र इशारा

जयपुर (विसं)। विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा अभद्र इशारा करते हुए कैमरे में कैद हो गए। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरिमोहन शर्मा विधायकों को सरकारी कार्यक्रमों के लोकार्पण शिलान्यास का मुद्दा उठा रहे थे। रोहित बोहरा उनके पीछे बैठे थे।

इस दौरान बोहरा ने किसी विधायक को हाथ जोड़कर अभिवादन किया, थोड़ी ही देर में उन्होंने हंसेते हुए हाथ से अभद्र इशारा किया था। यह सब विधानसभा की लाइव फीड के कैमरों में भी कैद हो गया था। हालांकि विधानसभा सदन में अब तक किसी विधायक ने इस पर चर्चा नहीं की थी। देर शाम सदन की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी।



भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र कटारा ने मुख्यमंत्री निवास पहुँचकर “बजट राजस्थान 2026-27” के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद व्यक्त किया। कटारा ने कहा कि यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ गरीब, किसान, नारी शक्ति और युवा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।

दौसा तहसीलदार की कार्यशैली पर विधानसभा में हंगामा

-विधानसभा संवाददाता- जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को दौसा तहसीलदार की कार्यशैली को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दौसा से कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने शून्यकाल के दौरान तहसीलदार पर मनमाणी और एससी वर्ग के लोगों के मकान तोड़ने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तहसीलदार बचिव तबके के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है और उनका व्यवहार भी अत्यंत खराब है। बैरवा ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार न केवल अपमानजनक है, बल्कि पूरे सदन के

■ कांग्रेस विधायक बैरवा वेल में पहुँचे तो स्पीकर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया

लिए चिंताजनक है। उन्होंने संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

मामले को लेकर सदन में माहौल उस समय गरमा गया जब विधायक बैरवा वेल में आकर नारेबाजी करने लगे। इस पर स्पीकर ने नाराजगी जताते हुए इसे अनुशासनहीनता करार दिया। उन्होंने बैरवा को मर्यादा में रहने की हिदायत दी

और आश्वासन दिया कि मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की कोशिश की, जिस पर सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति जताई। जिस पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस भी हुई। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया कि मुख्य सचेतक किस नियम के तहत बीच में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हंगामे के बीच स्पीकर ने स्थिति को संभालते हुए कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सदन की कार्यवाही के दौरान इस मुद्दे को लेकर काफी देर तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा।

फैक्ट्री से 1000 किलो साँस सीज

जयपुर। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान खाद्य सुरक्षा एवं और स्वास्थ्य टीम टीम ने गुरुवार को मुहाना मंडी स्थित मैसर्स श्री श्याम फूड इंडस्ट्री पर कार्यवाही कर मिलावट के संदेह पर एक हजार किलो साँस सीज किया।

सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि इस फैक्ट्री से उत्पादित श्री श्याम ब्रांड साँस का नमूना जांच रिपोर्ट में अनसफ पाया गया था। जिस पर टीम और रिसर्चलिंग के निर्देश पर टीम इस फैक्ट्री पर पहुँची। मौके पर टीम द्वारा स्नैक्स साँस और रेड चिली साँस के नमूने लेकर शेष एक हजार किलो साँस में कलर मिला होने एवं अन्य कोई मिलावट होने का संदेह होने पर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक सीज किया गया। मौके पर फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, साँस, आचार आदि लगभग 150 किलो एस्पायर पाए गए। जिन्हें मौके पर नष्ट करवाया गया।

विधानसभा में फिर गुंजा खेजड़ी संरक्षण का मुद्दा

विधायकों ने गौशालाओं, विधायकों के सम्मान और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े प्रकरण भी उठाए

जयपुर (विसं)। राज्य विधानसभा में गुरुवार को शून्यकाल के दौरान स्थान प्रस्ताव के जरिए विधायकों ने कई अहम मुद्दे उठाए। बायतू विधायक हरीश चौधरी ने खेजड़ी के संरक्षण का मामला प्रमुखता से उठाते हुए इसे प्रदेश की लाइफ लाइन बताया। वहीं अन्य विधायकों ने गौशालाओं, विधायकों के सम्मान और प्रशासनिक कार्यों से जुड़े मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

हरीश चौधरी ने कहा कि खेजड़ी का अस्तित्व संकट में है और बीकानेर

सहित कई क्षेत्रों में इसके संरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में लाखों खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। हम सब इस मामले में विफल रहे हैं, लेकिन अब मिलकर इसे रोकना होगा, उन्होंने कहा। चौधरी ने बताया कि टेनेसी एक्ट लागू होने के समय खेजड़ी एक प्रकार की संपत्ति मानी जाती थी, लेकिन आज यह प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी है।

चौधरी ने चर्चा के दौरान एक समाज विशेष का उल्लेख किया, जिस

पर विधायक पटेल ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यदि उनका नाम लिया जा रहा है तो उन्हें पहले नोटिस दिया जाना चाहिए।

इस बात को लेकर दोनों विधायकों के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए चौधरी को अध्यक्ष को संबोधित करने के निर्देश दिए। टोका-टाकी के बीच चौधरी ने कहा कि आवश्यकता होगी तो वे नोटिस देंगे। भी बात करेंगे, लेकिन खेजड़ी का संरक्षण अत्यंत जरूरी है।

6 करोड़ रुपए के गांजा तस्करी करने वाले को राहत नहीं

जयपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने बैंकाक से करीब छह करोड़ रुपए के हाईड्रोपोनिक वीड (गांजा) की तस्करी के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में आरोपी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस शुभा मेहता की एकलपीठ ने यह आदेश इज्जतुल कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने साधारण गांजा नहीं, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली और कई गुणा नशीला हाईड्रोपोनिक वीड की तस्करी की है। ऐसे मादक पदार्थ युवाओं को नशे का आदि बना रहे हैं।

‘नेता प्रतिपक्ष को फॉर्च्यूनर मिलने से हुई डोटासरा को तकलीफ’

भाजपा विधायक कैलाश वर्मा ने सदन में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पर कटाक्ष किया

जयपुर (विसं)। राजस्थान विधानसभा में बजट बहस के दौरान भाजपा विधायक कैलाश वर्मा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए कहा कि मंत्रियों के लिए वाहन हर सरकार में खरीदे जाते हैं, इसमें मुख्यमंत्री का कोई दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्रियों के लिए फॉर्च्यूनर ली गई तो डोटासरा को तकलीफ हो गई। यही फॉर्च्यूनर

मंत्रियों के साथ नेता प्रतिपक्ष को भी मिली है। मुझे लगता है उन्हें इस बात से ज्यादा परेशानी है कि नेता प्रतिपक्ष को यह सुविधा कैसे मिल गई।

इस टिप्पणी पर कांग्रेस विधायकों ने कड़ा विरोध जताया। हंगामे के बीच कैलाश वर्मा ने आपत्ति करने वाले विधायकों से कहा, मुझे क्या बोलना है, यह आप तय नहीं करेंगे, आपको सुनना पड़ेगा। विपक्ष

के विरोध के कारण सदन में कुछ देर तक शोर-शराबा रहा, जिसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ाई गई।

बजट पर चर्चा के दौरान कैलाश वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश को विरासत में कर्ज का बड़ा बोझ देकर गई है और वित्तीय स्थिति को बिगाड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने प्रदेश को आर्थिक रूप से कमजोर किया।

भजनलाल सरकार का तीसरा बजट “विकसित राजस्थान” का रोडमैप : डॉ. प्रेमचंद बैरवा



उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को बीजेपी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की।

जयपुर (कासं)। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को विकसित राजस्थान का रोडमैप बताया। बीजेपी ऑफिस में प्रेस वार्ता में डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमार द्वारा प्रस्तुत 6.10 लाख करोड़ रुपये का बजट, वर्ष

2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है। अवसरंचना विकास के लिए 53 हजार 978 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 32 हजार 526 करोड़ (53 प्रतिशत वृद्धि), शिक्षा क्षेत्र में 69 हजार करोड़ (35 प्रतिशत वृद्धि), कृषि बजट में 7.59 प्रतिशत और ग्रीन बजट में 20.81 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान

किया गया है। 400 विद्यालयों को सीएम राज्ज विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जाएगा तथा राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा की गई है। युवाओं के लिए 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 1 लाख पदों का भी कैंडलैड जारी किया गया है।

किसानों को 25 हजार करोड़ रुपए के ऋण वितरण और 800

करोड़ ब्याज अनुदान का प्रावधान है। शेखावाटी तक यमुना जल लाने के लिए 32 हजार करोड़ की परियोजनाएं शुरू होंगी।

जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बजट 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना के अनुरूप 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आधार स्तंभ साबित होगा।

डीजीपी राजीव शर्मा ने ली पुलिस और पर्यटन विभाग की बैठक



पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने गुरुवार को पुलिस और पर्यटन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश में पर्यटक सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की।

जयपुर। राजस्थान आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजामों के लिए गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पुलिस व पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। डीजीपी ने प्रदेश में विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए पर्यटन स्थलों पर स्थापित पर्यटक सहायता बल (टीएएफ) को और सुदृढ़ करने, पर्यटन थायों की संख्या बढ़ाने और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए अपेक्षित पुलिस बल लगाने और इन्हें उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश दिए।

उन्होंने हाल ही में पर्यटन विकास के लिए बजट में दी गई स्वीकृति पर कार्ययोजना तैयार करने व पर्यटन स्थलों पर विशेष त्योहारों, मेलों के साथ-साथ सामयिक आयोजनों में भी पर्यटन विभाग की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य भर के विभिन्न धार्मिक पर्यटन स्थलों तथा खादू श्यामजी, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी, रामदेवरा, गोमामेड़ी, पुष्करजी, श्रीनाथद्वारा, सांवरियाजी आदि में कुशल प्रबंधन के लिए देवस्थान, पुलिस व प्रशासन मिलकर कार्य करें और पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्थाएं करें।

बैठक में डीजी (ट्रेफिक) अनिल पालीवाल ने पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए की

जाने वाली व्यवस्थाओं के साथ-साथ विभिन्न दूतावासों से संपर्क कर पर्यटन आमंत्रण की बात कही। आईजी अजयपाल लांबा ने डीजी-आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए राज्य के पर्यटन स्थलों पर अन्य राज्यों के पुलिस अधिकारियों को नियोजित करने, एक ही स्थान पर समस्त सरकारी कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, पर्यटन स्थलों पर अधिकाधिक सीसीटीवी कवरेज करने, पांच डेस्टिनेशन जहां सबसे ज्यादा टय्यूरिस्ट आते हैं वहां पर्यटन थाना बनाने, टयूरिज्म के नेशनल पोर्टल पर राज्यों के पोर्टल को लिंक करने आदि के सुझावों की जानकारी दी। बैठक में पर्यटन आयुक्त रूकमणि रियाड ने पर्यटन स्थलों की वर्तमान स्थिति और यहां पर विभाग द्वारा पर्यटकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पर्यटकों की सुविधा को देखते हुए विभाग द्वारा तैयार की गई प्रचार सामग्री, बुथ डिजाइन, प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में जानकारी दी।

खादूश्यामजी मेले में विशेष प्रबंध करें

डीजीपी शर्मा ने खादूश्यामजी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए पर्यटन पुलिस और टीएएफ की ओर से विशेष प्रबंध किए जावें।

उन्होंने पर्यटकों की सुविधा के लिए जगह-जगह पुलिस सहायता प्राप्त करने के लिए नियंत्रण कक्ष नंबर, पुलिस हेल्पलाइन 112, राजकाप सिटीजन एप आदि के लिंक इत्यादि दर्शाती हुई स्टैंडीज व टीएएफ की ओर से विशेष सहायता वृथ स्थापित करने के निर्देश दिए और कहा कि टीएएफ की उपस्थिति दिखनी चाहिए।

पर्यटकों को मिले बेहतर सुविधाएं : डीजीपी ने पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुरूप अमेर की केस स्टडी में आई अपेक्षाओं को समस्त पर्यटक स्थलों पर लागू करने की बात कही। उन्होंने सभी पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा के साथ-साथ पर्यटकों को स्वच्छ वातावरण और आवागमन के लिए व्यवस्थित सड़क सुविधा के साथ-साथ पर्यटकों के लिए अपेक्षित सुचनाओं की उपलब्धता के संबंध में उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों के साथ-साथ रेल्वे स्टेशन, हवाई अड्डा और अन्य स्थानों पर पर्यटकों की सुविधा के लिए पर्यटक सहायता वृथ स्थापित हो जहां पर पर्यटक किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल संपर्क कर सकें। बैठक में एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) वी.के.सिंह, एडीजी (ट्रेफिक) बीएल मीणा सहित पर्यटन, आरटीडीसी,आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण, नगर निगम और संबंधित पुलिस अधिकारी मौजूद थे।

